



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 255]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 22, 2003/आश्विन 30, 1925

No. 255]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22, 2003/ASVINA 30, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2003

अंतिम जांच परिणाम

विषय : जर्मनी एवं कोरिया गणराज्य से सोडियम हाइड्रोसल्फाईट के आयातों संबंधित पाटनरोधी जांच।

सं. 14/34/2002 डी.जी.ए.डी.—वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और उसकी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आंकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण)नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए ;

क. प्रक्रिया

1. जांच के बारे में नीचे निर्धारित प्रक्रिया अपनायी गयी है :—

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) ने घरेलू उद्योग की ओर से उपर्युक्त नियम के अनुसार मै. ट्रांसपेक सिलोक्स इंडस्ट्री लि., वडोदरा और मै. देमोशा कैमिकल्स प्रा. लि., मुम्बई (जिन्हें इसमें इसके बाद याचिकाकर्ता कहा गया है) द्वारा

- प्रस्तुत एक याचिका प्राप्त की थी जिसमें जर्मनी एवं कोरिया गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रोसल्फाइट के पाटन का आरोप लगाया गया था ।
- (ii) प्राधिकारी ने जर्मनी एवं कोरिया गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध माल के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरु करते हुए भारत के राजपत्र में दिनांक 14-11-2002 को प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी ।
- (iii) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसमें इसके बाद प्राधिकारी भी कहा गया है) ने जर्मनी ओर कोरिया गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रोसल्फेट के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांचों के बारे में दिनांक 25 फरवरी, 03 की अधिसूचना सं. 14/34/2002-डी.जी.ए.डी. द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचित किए थे और हितबद्ध पक्षकारों से इसके प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया था ;
- (iv) प्राधिकारी ने ज्ञात हितबद्ध पक्षों को प्रारंभिक जांच परिणामों की प्रति भेजी और उन्हें परिणामों पर अपने विचार यदि कोई हों, को पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर देने का आग्रह किया ;
- (v) प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों की एक प्रति नई दिल्ली स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों / उच्चायोगों / प्रतिनिधियों को भी भेजी थी और उनसे प्रारंभिक जांच परिणामों पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था ;
- (vi) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षों को मौखिक रूप से सुनने के लिए 5 मई, 2003 को एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जिसमें घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों , संबद्ध देश के आयातकों एवं निर्यातकों ने भाग लिया । सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने वाली सभी पार्टियों कोए मौखिक रूप से प्रस्तुत किए गए विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया । हितबद्ध पक्षकारों से इस प्रकार प्राप्त लिखित अनुरोधों को प्राधिकारी द्वारा इन निष्कर्षों पर विचार किया गया है ;

- (vii) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंशों को सार्वजनिक फाईल के रूप में; नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पार्टियों द्वारा जांच के लिए खुला रखा;
- (viii) सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जी ए ए पी) और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु को बनाने और बेचने तथा उत्पादन की इष्टतम लागत निकालने के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत का विश्लेषण किया गया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटन शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा । निम्नलिखित कम्पनियों के लागत आंकड़े प्रस्तुत किए गए तथा उनकी जांच की गई :-

1. मै. ट्रांसपेक सिलोक्स इंडस्ट्री लि., वडोदरा
2. मै. दीमोशा केमिकल्स प्रा. लि., मुंबई

- (ix) प्राधिकारी ने आवश्यक समझी गयी सीमा तक घरेलू उद्योग का मौके पर सत्यापन किया ;
- (x) उपर्युक्त नियम 16 के अनुसार इन जांच परिणामों के लिए विचार किए गए आवश्यक तथ्य / आधार (घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत) तथा उन पर प्राप्त टिप्पणियों को ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को प्रकट किया गया, इन जांच परिणामों में विधिवत् रूप से विचार किया गया है ;
- (xi) यह जांच 1 अप्रैल, 2001 से 30 सितम्बर, 2002 अर्थात् जांच की अवधि के लिए की गई थी ;
- (xii) यह **** चिह्न इस अधिसूचना में हितबद्ध पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का द्योतक है तथा नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी ने इसे गोपनीय ही माना है ।

ख. विचाराधीन उत्पाद / समान वस्तु

2. जांचाधीन उत्पाद सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के नाम से जाना जाता है। यह तीखी सी गंध वाला सफेद या ग्रे रंग का रवेदार पाउडर है तथा किसी भी दृष्टिगोचर बाहरी कणों से मुक्त है। इसका आयात सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 28 एवं 29 के अंतर्गत किया गया है।

3. जहां तक विनिर्माण प्रक्रिया का संबंध है, याचिकाकर्ता संबद्ध माल का उत्पादन करने के लिए जिक एवं फॉरमेट विधि का प्रयोग करते हैं। यह प्रक्रिया विश्व भर में स्वीकार्य है और विश्व भर के विनिर्माताओं द्वारा अपनायी जाती है। वस्तुतः मै. बी ए एस एफ द्वारा अंगीकृत अमलगम प्रक्रिया को, प्रक्रिया में मरकरी के उपयोग को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध ढंग से समाप्त किया जा रहा है। तथापि, प्रौद्योगिकी चाहे कुछ भी हो, अंतिम उत्पाद तुलनीय एवं तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है।

4. निर्यातक ने यह दावा किया है कि भारतीय उत्पादों की तुलना में उनके उत्पाद को अधिक पसंद किया जाता है। याचिकाकर्ताओं का यह भी निवेदन कि (क) यह एक वस्तु है, जो वास्तविक रूप से सही नहीं है; (ख) निर्यातक एक लम्बी अवधि से इसका बड़ी मात्रा में निर्यात नहीं कर रहा है इसलिए पसंद का प्रश्न नहीं उठता है; (ग) जब चीन से आयात किया जा रहा है तो पसंद नहीं हो सकती है; (घ) आयातों में वृद्धि होने का कारण कीमतों में कमी है; (ङ) यह बी ए एस एफ द्वारा पेशकश की गयी कीमत है न कि ग्राहकों की पसंद जैसाकि ग्राहक-वार बिक्री विवरण के ब्यौरे में देखा जा सकता है; और (च) दूसरे उत्पाद की तुलना में एक उत्पाद की पसंद का अर्थ यह है कि दोनों समान वस्तुएं हैं।

मै. बी ए एस एफ के विचार

5. विश्व भर में दो भिन्न-भिन्न उत्पादन प्रक्रियाएं हैं। बी ए एस एफ अमलगम प्रक्रिया से सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन करता है। हमारे "हाइड्रोसल्फिट एन" ब्राण्ड में डस्ट बाइंडिंग एजेंट होता है जो जल में पूर्णरूपेण घुलनशील होता है। इसीलिए इसकी मांग स्थानीय

विनिर्मित उत्पाद की अपेक्षा अधिक है । स्थानीय विनिर्मित उत्पाद में डस्ट बाइंडिंग एजेंट के रूप में खनिज तेल होता है जो जल में पूर्ण घुलनशील नहीं होता है ।

6. हैरिमेन केमसल्ट के प्रकाशन में यह लिखा हुआ है कि देमोशा ज़िंक प्रक्रिया का उपयोग कर रहा है और दूसरा याचिकाकर्ता सिलोएक्स ज़िंक और फोरमेट दोनों प्रक्रियाओं का उपयोग कर रहा है । यह कथन कि भारतीय उद्योगों द्वारा अपनायी गयी प्रौद्योगिकी जर्मनी एवं कोकिया गणराज्य में सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के विनिर्माताओं के साथ तुलनीय है, पूर्ण रूप से गलत एवं भ्रामक है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

7. जांचाधीन उत्पाद सोडियम हाइड्रोसल्फाइड है (जिसे इसके बाद से संबद्ध वस्तुएं कहा जाएगा)। यह तीखी सी गंध वाला सफेद या ग्रे रंग का रवेदार पाउडर है तथा किसी भी दृष्टिगोचर बाहरी कणों से मुक्त है । इसका आयात सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 28 एवं 29 के अंतर्गत किया गया है । वर्गीकरण उपशीर्ष 2831.1001 तथा 2832.1002 भले ही इसका वर्णन सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के रूप में करें परंतु सही सीमाशुल्क वर्गीकरण 6 अंकों वाले उपशीर्ष 2831.10 का माना जाएगा तथा यह सोडियम सल्फाइड कहा जाएगा । तथापि वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा वर्तमान जांच के क्षेत्र पर किसी भी प्रकार बाध्यकारी नहीं है । प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि इस जांच में विचाराधीन उत्पाद के रूप में सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के सभी रूप शामिल हैं ।

8. भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित सोडियम हाइड्रोसल्फाइड तथा जर्मनी एवं कोरिया से निर्यातित सोडियम हाइड्रोसल्फाइड में ऐसा कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं है जो कि कीमत को प्रभावित कर सके । भारतीय उद्योग द्वारा विनिर्मित सोडियम हाइड्रोसल्फाइड जर्मनी तथा कोरिया से आयातित सोडियम हाइड्रोसल्फाइड भौतिक तथा रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया तथा प्रौद्योगिकी, कार्य तथा प्रयोग, उत्पाद विशिष्टिकरण, कीमत, वितरण तथा विपणन एवं वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संबंध में तुलनीय है । दोनों का तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रतिस्थापन किया जा सकता है । उपभोक्ताओं ने दोनों को एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया

है । पाटनरोधी नियमावली के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा निर्मित उत्पादित सोडियम हाइड्रोसल्फाइड तथा जर्मनी एवं कोरिया से आयातित सोडियम हाइड्रोसल्फाइड को समान वस्तुएं माना जाना चाहिए । भारतीय उद्योग द्वारा अपनाई जा रही प्रौद्योगिकी जर्मनी और कोरिया में सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के विनिर्माताओं द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी से तुलनीय है ।

9. इस प्रकार प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं और संबद्ध देशों से निर्यात की जा रही वस्तुएं नियम 2 (घ) के अर्थों के भीतर समान वस्तु हैं ।

ग. घरेलू उद्योग

10. पाटनरोधी नियमों के नियम 2(घ) के अनुसार, "घरेलू उद्योग का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु का विनिर्माण और उससे जुड़ा कोई कार्यकलाप करते हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है किन्तु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा ।" इसके अतिरिक्त पाटनरोधी नियमों के नियम 5(3) में यह उल्लेख है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी उपनियम (1) के तहत किए गए किसी आवेदन के अनुसरण में तब तक कोई जांच आरंभ नहीं करेगा जब तक कि वह समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों द्वारा आवेदन के समर्थन अथवा उसके विरोध के स्तर की जांच के आधार पर यह निर्धारित न कर ले कि उक्त आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किया गया है किन्तु उस स्थिति में कोई जांच शुरू नहीं की जाएगी यदि उक्त आवेदन का समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के कुल उत्पादन के 25% से कम बनता है ।

11. मै. ट्रांसपेक सिलोक्स इंडस्ट्री लि. और मै. देमोशा कैमिकल्स प्रा. लि. ने घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर की है । ये याचिकाकर्ता कंपनियां उत्पादन के अधीन संबद्ध वस्तु के 54.80% का प्रतिनिधित्व करती हैं ।

12. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उत्पादकों का कुल घरेलू उत्पादन में 50% से अधिक हिस्सा बनता है और किसी घरेलू उत्पादक द्वारा याचिका का विरोध नहीं किया गया है, इस प्रकार वे पाटनरोधी नियमों के नियम 5(3)(क) और (ख) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने और नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने की भी स्थिति में हैं।

यूरोपीय संघ के विचार

13. यूरोपीय आयोग पाता है कि प्रारंभिक जांच परिणाम डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार में निर्धारित अपेक्षाओं, विशेष रूप से पाटन संबंधी अनुच्छेद 2 और क्षति संबंधी अनुच्छेद 3.4 तथा 3.5 को पूरा नहीं करते हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटन की मौजूदगी को प्रकट करने में असफल रहे हैं, सभी संगत आर्थिक कारकों की जांच की अनदेखी की है और कथित पाटित आयातों और घरेलू उद्योग की वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की मौजूदगी की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। अंत में यूरोपीय आयोग पाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य कारकों की मौजूदगी और कथित क्षति पर उसके प्रभाव को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में असफल रहा है।

14. यूरोपीय आयोग को यह नोट करते हुए आश्चर्य हुआ है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी महत्वपूर्ण शेष घरेलू बिक्री (गैर शिकायातकर्ता उद्योग की) की गणना करने में पूरी तरह असफल रहा है, जो औसतन कुल घरेलू खपत के 40% का प्रतिनिधित्व करती है। घरेलू उद्योग में स्थिति का उचित और संपूर्ण परिदृश्य देने के उद्देश्य से बिक्री की प्रवृत्ति और शेष घरेलू उत्पादकों से बाजार हिस्से की जांच की जानी चाहिए।

15. आयोग इस तथ्य को इंगित करना चाहेगा कि याचिकाकर्ता का बाजार हिस्सा 1999/00 से जांच अवधि तक 5.24 % अंकों तक गिरा है जबकि इसी अवधि में कथित पाटित आयात केवल 0.84% अंकों तक बढ़े हैं। इससे कुल 4.41% अंकों की गणना शेष रह जाती है। यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के बाजार हिस्से की हानि अन्ततः उद्योग प्रतिस्पर्धा के कारण हुई है और न कि कथित पाटित आयातों के कारण, जो प्रभावी रूप से पाटित आयातों और क्षति के बीच किसी कारणात्मक संबंध को तोड़ देगा।

प्राधिकारी की जांच

16. प्राधिकारी ने सहयोगी और गैर-सहयोगी निर्यातकों दोनों के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित किया है। चूंकि भारतीय पाटनरोधी नियमों में कम शुल्क का प्रावधान है और इसलिए सहयोगी और गैर-सहयोगी निर्यातकों के लिए नाममात्र का पाटन मार्जिन अलग-अलग है, इसलिए दोनों के लिए बेंचमार्क अभी भी समान हो सकता है।

17. जहां तक अनुच्छेद 3.4 और अनुच्छेद 3.5 के अन्तर्गत क्षति के कारकों की जांच का संबंध है, प्राधिकारी घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संबंधी मापदंडों की उनकी लागत और वित्तीय सूचना के आधार पर जांच करते हैं। इन्हीं मापदंडों में सुधार के संबंध में यह इंगित करना अनिवार्य होगा कि कुछेक मापदंडों में सुधार से यह संकेत नहीं मिलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हुई है। यह सिद्ध करने के लिए कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है, एक मापदंड भी पर्याप्त होगा। मांग में बाजार हिस्से के संबंध में यह नोट किया गया है कि याचिकाकर्ता कंपनियों का संपूर्ण लागत सूचना के साथ घरेलू उत्पादन में 50% से अधिक का हिस्सा बनता है। क्षति मापदंडों की इन जांच परिणामों के क्षति और कारणात्मक संबंध संबंधी अलग खण्ड में विस्तार पूर्वक जांच की गई है।

18. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इस बात की चिंता करने का कोई कारण नहीं है कि घरेलू उद्योग को क्षति अन्य भारतीय उत्पादकों के कारण हो सकती है। इसके विपरीत इसके सकारात्मक साक्ष्य है कि घरेलू उद्योग ने पाटित आयातों के कारण बाजार हिस्सा खो दिया है, आयात कीमतों में भारी गिरावट के कारण कीमतों में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग का प्रतिकूल निष्पादन पाटित आयातों के कारण है। चूंकि भारतीय पाटनरोधी नियमों में कम शुल्क का प्रावधान है इसलिए उच्च उत्पादन लागत के कारण ऐसा कोई प्रभाव स्वतः ही प्रतिबंधित हो जाएगा।

घ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

19. धारा 9 क (1)(ग) के अधीन किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है :-

- (i) सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तुओं के लिए उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियम के अनुसार यथा निर्धारित तुलनात्मक मूल्य जबकि ऐसी वस्तु निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए आशयित हो ;
- (ii) जहां निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं हो या विशेष बाजार दशा के कारण अथवा निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्रियों की कम मात्रा के कारण ऐसी बिक्रियों की बजह से समुचित तुलना नहीं हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
- (क) निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से आयात किए जाने पर समान वस्तु की उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा निश्चित तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य ; या
- (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा निश्चित प्रशासनिक बिक्री और सामान्य लागतों एवं लाभों के लिए उचित वृद्धि के साथ वस्तु मूल के देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत ;

घरेलू उद्योग के विचार

20. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जर्मनी तथा कोरिया के ज्ञात निर्यातकों / उत्पादकों को और भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को प्रश्नावली भेजी थी । तथापि, मात्र जर्मनी के मै. बी ए एस एफ ने प्राधिकारी को उत्तर दिया है । निर्यातक द्वारा दायर किया गया पूरी तरह त्रुटिपूर्ण और अपर्याप्त था जैसा कि प्रारंभिक जांच परिणामों से स्पष्ट है । प्रकटन विवरण से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या निर्यातक ने जांच अवधि के लिए लाभ तथा हानि लेखा प्रस्तुत किया है । इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक जांच परिणाम में यह स्वीकार किया गया है कि निर्यातक ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत प्रस्तुत नहीं की है । प्रकटन विवरण से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या निर्यातक ने उत्पादन लागत उपलब्ध कराई है और क्या प्रस्तुत की गई उत्पादन लागत जांच अवधि के लिए है ।

21. कोरिया गणराज्य के संबंध में, कोरिया में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । अतः, पहले याचिका में घरेलू उद्योग द्वारा किया गया दावा और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रारंभिक जांच परिणाम अब अखण्डित हैं । ऐसे मामले में, याचिकाकर्ता निर्दिष्ट प्राधिकारी से प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि करने का निवेदन करते हैं ।

22. बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां वस्तु का आयात उद्गम*वाले देश से इतर किसी देश से किया गया हो तथा जहां वस्तु को निर्यात वाले देश से होकर केवल वाहनान्तरित किया गया हो या ऐसी वस्तु का निर्यात वाले देश में उत्पादन नहीं किया जाता हो या निर्यात वाले देश में कोई भी तुलनात्मक कीमत नहीं हो तक सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में इसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा ।

23. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के निर्यातकों को उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार जांच के संगत सूचना प्रस्तुत करने और अभ्युक्तियां, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया था । प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावासों / उच्चायोगों / प्रतिनिधि को भी लिखा था । प्राधिकारी ने सीमाशुल्क अधिनियम के अनुच्छेद 9 क (1) (ग) के अनुसार निर्यात कीमत तथा सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थीं । मात्र मै. सोल्वे बेल्जियम द्वारा उत्तर दायर किए गए थे जो कि अपूर्ण थे । किसी निर्यातक ने प्रारंभिक जांच परिणामों का उत्तर नहीं दिया और पाटन अथवा क्षति के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की ।

निर्यातक (मै. बी ए एस एफ, जर्मनी) के विचार

24. निर्यातक ने बिक्री तथा विपणन लागतों के लिए समायोजन का दावा किया था परन्तु दावे के लिए कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया था और इसलिए ऐसे अप्रमाणित दावों को अस्वीकृत कर दिया गया था । नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 2 के अनुसार विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्रियों की तुलना उत्पादन लागत योग प्रशासनिक बिक्री तथा सामान्य लागतों से की गई थी, जिन्हें निर्यातों, घरेलू बिक्रियों और तीसरे देशों को किए जाने वाले निर्यातों के लिए अलग से उपलब्ध कराया गया था ।

यद्यपि माननीय प्राधिकारी ने अपने वक्तव्य में उल्लेख किया है कि विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्रियों की तुलना उत्पादन लागत योग प्रशासनिक बिक्री और सामान्य लागतों से की गई है जिन्हें निर्यातों, घरेलू बिक्रियों और तीसरे देशों को किए जाने वाले निर्यातों के लिए जलग से उपलब्ध कराया गया था, लेकिन घरेलू बिक्रियों के लिए बिक्री तथा वितरण लागतों के लिए समायोजन की अनुमति नहीं दी गई है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

जर्मनी

मै. बी ए एस एफ, जर्मनी

25. मै. बी ए एस एफ लेखापरीक्षित लेखा रखने हैं और कैलेण्डर वर्ष कंपनी का लेखा वर्ष है । संपूर्ण बी ए एस एफ लेखे यूरो मुद्रा में रखे जाते हैं । कंपनी एस ए पी पर अपने लेखे रखती है । अलग-अलग उत्पादों को अलग उत्पाद केन्द्र माना जाता है और प्रत्येक उत्पाद के लिए लाभप्रदता का मूल्यांकन अलग से किया जाता है । यद्यपि जांच अवधि निर्यातक द्वारा रखे गए लेखा वर्ष से भिन्न थी, फिर भी एस ए पी से जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत प्राप्त करना संभव था ।

सामान्य मूल्य

26. कंपनी ने जांच अवधि के लिए सोडियम हाइड्रोसल्फाइट की घरेलू बाज़ार में की गई बिक्रियों के सौदावार ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं । इस सूचना का बिक्री संबंधी मूल रिकॉर्डों और बीजकों के साथ सत्यापन किया गया था और इसे सही पाया गया था । कंपनी ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाज़ार में 4263 मी टन सोडियम हाइड्रोसल्फाइट बेचा है । यह भी देखा गया है कि सभी घरेलू बिक्रियां सी आई एफ स्तर पर की गई हैं । कारखाना द्वार स्तर पर बिक्री के मूल्यांकन के लिए निर्यातक ने इन व्यापार सौदों में कुछेक समायोजनों का दावा किया है । बिक्री एवं विपणन लागतों के संबंध में समायोजन के निर्यातक के दावे पर विचार नहीं किया गया था क्योंकि मौके पर

सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान इसे न तो न्यायसंगत पाया गया और न ही इन्हें सही साबित किया गया, इसलिए उनके घरेलू बाजार में घरेलू बिक्रियों की कारखाना द्वार पर लागत को ज्ञात करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी द्वारा ऐसे खोखले दावों को अस्वीकार कर दिया गया था । नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 2 के अनुसार विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्रियों की तुलना उत्पादन लागत जमा बिक्री, प्रशासनिक एवं सामान्य लागतों लिन्हें भारत, घरेलू बिक्रियों तथा तीसरे देशों को हुए निर्यातों के लिए अलग-अलग उपलब्ध कराया गया था, के साथ की गई थी । घरेलू बाजार में घरेलू बिक्रियों को व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में पाया गया था । कंपनी ने चालू वर्ष और पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए लाभ एवं हानि लेखों की प्रतियों तथा तुलन पत्र की प्रतियां उपलब्ध कराई थीं जिनमें सकल लाभ, बिक्री एवं प्रशासनिक एवं अन्य लागतों तथा निवल लाभ के निर्धारण को दर्शाया गया था । उत्पादन लागत का निर्धारण किया गया था और घरेलू बिक्रियों के साथ इसकी तुलना की गई थी और यह पाया गया है कि सभी बिक्री सौदे उत्पादन लागत से अधिक पर हुए हैं और इसलिए ये व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में थे । इसलिए सामान्य मूल्य घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की औसत बिक्री वसूली पर आधारित है । कारखाना द्वार पर घरेलू बिक्री कीमत को ज्ञात करने के लिए पैकिंग, भाड़े, भण्डारण एवं प्रहस्तन के संबंध में समायोजनों पर विचार किया गया है ।

27. प्राधिकारी ने मै. बी ए एस एफ के लिए सामान्य मूल्य **** अमरीकी डॉलर / मी. टन निर्धारित किया है ।

निर्यात कीमत

28. निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान भारत को किए गए निर्यातों के बीजक-वार ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं । प्रस्तुत की गई सूचना का मूल रिकॉर्डों एवं बीजकों के साथ सत्यापन किया गया था । निर्यातक ने प्रश्नावली के अपने जवाब और उसके बाद के स्पष्टीकरण में अनुरोध किया था कि भारत को किए गए निर्यात यूरो में हैं । तथापि सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान यह देखा गया था कि निर्यात अमरीकी डॉलर में किए गए थे और निर्यातक ने प्रश्नावली के परिशिष्ट 2 में संशोधित सूचना प्रस्तुत की थी । मै बी ए एस एफ ने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का 840

मी. टन बेचा है। भारत को की गई बिक्रियों को मै. बी ए एस एफ, लुडविगशेफन, जर्मनी से सीधे भारतीय ग्राहक को जलयान द्वारा भेजा गया है। सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान यह भी देखा गया था कि जांच अवधि के दौरान निर्यातक द्वारा भारत में केवल मै. रामानन्द किदारनाथ इंटरनेशनल को विचाराधीन उत्पाद की सुपुर्दगी / बिक्री की गई थी। बी एस ई ए, सिंगापुर द्वारा बीजक तैयार किए गए थे। ग्राहक उपलब्ध कराने के लिए बी ए एस एफ, भारत को 3% का कमीशन मिलता है। बी एस ई ए, सिंगापुर को बीजक बनाने, प्राप्यों को प्राप्त करने, अन्य प्रसंस्करण आदि के लिए 3.5% कमीशन मिलता है। निर्यातक ने सिंगापुर और भारत में अपनी संबद्ध फर्मों को दिए गए इन कमीशनों के संबंध में समायोजनों का दावा किया है। यह देखा गया है कि बिक्रियां सी आई एफ स्तर पर की गई थी और अंतर्देशीय भाड़े, प्रहस्तन प्रभारों आदि के लिए किए गए समायोजनों का उनकी प्रणाली से सत्यापन किया गया था और इन्हें सही पाया गया था।

29. अतः प्राधिकारी मै. बी ए एस एफ, जर्मनी के लिए कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत **** अमरीकी डॉलर / मी. टन निर्धारित की थी।

जर्मनी के अन्य निर्यातक / उत्पादक

सामान्य मूल्य

30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. बी ए एस एफ के आलावा जर्मनी के किसी निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है। प्राधिकारी ने असहयोग के मद्देनजर, सभी अन्य उत्पादकों / निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन सहयोगी निर्यातकों के लिए उपलब्ध अनुमानित लागतों और पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया है।

31. इस प्रकार सामान्य मूल्य को **** डॉलर / मी. टन संदर्भित किया गया है।

निर्यात कीमत

32. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यात कीमत का निर्धारण डी जी सी आई एंड एस, कोलकाता से प्राप्त सांख्यिकीय सूचना के आधार पर किया गया है। जर्मनी से सहयोगी निर्यातकों

/ उत्पादकों के समायोजनों के आधार पर समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़े तथा पत्तन व्ययों के लिए क्रमशः **** अमरीकी डॉलर / मी. टन, **** अमरीकी डॉलर / मी. टन, **** अमरीकी डॉलर / मी. टन, **** अमरीकी डॉलर / मी. टन तथा **** अमरीकी डॉलर / मी. टन की सीमा तक समायोजन का अनुमान लगाया गया है ।

33. कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत **** अमरीकी डॉलर / मी. टन संदर्भित की गई है ।

कोरिया, आर. पी.

सामान्य मूल्य

34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया से किसी भी निर्यातक ने जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना या प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद प्रश्नावली के माध्यम से उत्तर नहीं दिया है । प्राधिकारी ने इस असहयोग के मद्देनजर, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सभी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है । इसलिए कोरिया में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयाजनार्थ आवश्यक समायोजनों के साथ उत्पादन की परिकलित लागत को संदर्भित किया गया है ।

35. अतः सामान्य मूल्य **** डॉलर / मी. टन संदर्भित किया गया है ।

निर्यात कीमत

36. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यात कीमत का निर्धारण डी जी सी आई एंड एस, कोलकाता के आंकड़ों के आधार पर किया गया है । चूंकि निर्यातकों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा यथा प्रदत्त समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़े तथा पत्तन व्ययों के लिए क्रमशः **** अमरीकी डॉलर / मी. टन, **** अमरीकी डॉलर / मी. टन, **** अमरीकी डॉलर / मी. टन, **** अमरीकी डॉलर / मी. टन तथा **** अमरीकी डॉलर / मी. टन के समायोजनों पर विचार किया गया है ।

37. कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत **** अमरीकी डॉलर / मी. टन संदर्भित किया गया है ।

पाटन मार्जिन - सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच तुलना

38. तुलना से संबंधित नियमों में निम्नानुसार व्यवस्था है :-

39. "पाटन मार्जिन निकालते समय, निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच उचित तुलना करेगा । यह तुलना व्यापार के उसी स्तर पर सामान्यतया कारखाना द्वार स्तर पर की जाएगी और यथासंभव उसी समयावधि के दौरान की गयी बिक्रियों के संबंध में की जाएगी। जो अंतर तुलनीयता पर प्रभाव डालते हैं, उनके लिए प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर समुचित छूट भी जाएगी, अंतर में शामिल हैं - बिक्री की शर्तें, कराधान, व्यापार के स्तर, मात्राएं, वास्तविक विशेषताएं तथा कोई अन्य अंतर जो कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं ।"

40. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I में यथा उल्लिखित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण को अधिशासित करने वाले सिद्धांतों को अपनाने की संगत नीति का अनुपालन किया है । ऊपर यथा इंगित सामान्य मूल्यों एवं निर्यात कीमतों के आधार पर प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से सभी निर्यातकों / उत्पादकों के मामले में पाटन मार्जिनों का मूल्यांकन किया है जैसा कि निम्नांकित तालिका में दिया गया है :-

निर्यातक / उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार बनता है :-

निर्यातक / उत्पादक	सामान्य मूल्य अमरीकी डॉलर/मी.टन	निर्यात कीमत अमरीकी डॉलर/मी.टन	निर्यात कीमत के % रूप में पाटन मार्जिन
जर्मनी			
(i) मै. बी ए एस एफ	****	****	22.97%
(ii) सभी अन्य निर्यातक / उत्पादक	****	****	35.55%
कोरिया आर.पी.			
सभी निर्यातक / उत्पादक	****	****	98.01%

उपर्युक्त पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है ।

इ. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

41. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में दिए गए क्षति के निर्धारण संबंधी सिद्धांतों में उल्लेख किया गया है कि :

- (i) क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा तथा समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव तथा (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव, दोनों की वस्तुपरक जांच शामिल होगी ।
- (ii) पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत की तुलना में काफी वृद्धि हुई है । नियम 19 के उपनियम (2) में यथा उल्लिखित कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा काफी हद तक कीमतों में कमी लाना अथवा कीमत में उस वृद्धि को रोकना है जो कि अन्यथा काफी हद तक बढ़ गई होती । भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमों के अनुबंध II (iv) के अनुसार ऐसे संकेतकों पर विचार किया है जो उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं जैसे:- उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन इत्यादि ।

क्षति का संचयी आंकलन

42. नियमावली के अनुबंध II के नियम (iii) के अनुसार यह अपेक्षित है कि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के आयातों के मामले में जब पाटनरोधी जांच एक साथ की जा रही है तो प्राधिकारी इस प्रकार के आयातों का संचयी रूप से आंकलन करेगा । तथापि, इस प्रकार का आंकलन तभी किया जा सकता है जब यह निर्धारित हो जाए कि प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त 2 प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक

देश से हुए आयातों की मात्रा भारत में समान वस्तु के आयात का 3 प्रतिशत है अथवा जहां प्रत्येक देश का निर्यात 3% से कम है वहां संचयी रूप से आयात समान वस्तु के आयातों का 7% से अधिक बनता है ; और आयातों के प्रभाव का संचयी आंकलन, आयातित वस्तु तथा समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों की दृष्टि से उचित है ।

मै. बी ए एस एफ के विचार

43. निम्नलिखित विश्लेषण के अनुसार वास्तविक क्षति के दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए गए आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं :

- (i) वर्ष 1999-2000 से जांच अवधि तक घरेलू बिक्री में केवल 4.63% तथा वर्ष 2000-01 से जांच अवधि तक केवल 1.23% तक की गिरावट आई है ।
- (ii) प्रति यूनिट उत्पादन लागत में 100 (1999-2000) से 98.45 (2000-01) से 93.31 (जांच अवधि) तक गिरावट आई है ।
- (iii) जबकि उसी अवधि में लाभप्रदता में 100 (1999-2000) से 100.14 (2000-01) तथा 100.16 (जांच अवधि) तक वृद्धि हुई है ।
- (iv) कथित पाटित आयातों से, जो कुल घरेलू खपत का केवल 2.5% है, से याचिकाकर्ताओं पर किस तरह उल्लेखनीय प्रभाव पड़ सकता है, जो घरेलू खपत का 48% है ।
- (v) शेष घरेलू उद्योग में बिक्री की प्रवृत्ति तथा बाजार हिस्सा जो कुल खपत का औसतन 40% है, का भी निरीक्षण किया जाए ।
- (vi) 1999-2000 से जांच अवधि के दौरान, याचिकाकर्ताओं के बाजार हिस्से में 5.24% की गिरावट आई है जबकि कथित आयातों में केवल 0.84% की वृद्धि हुई है । जिसमें से कुल 4.41% का कोई हिसाब मौजूद नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के बाजार हिस्से को क्षति, इंट्रा-इंडस्ट्री के पूर्ण होने के कारण हुई है ।

घरेलू उद्योग के विचार

44. इस मामले में संचयी मूल्यांकन के लिए मानदंड पूर्णतया सही हैं । किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस का विराध नहीं किया है । इसलिए, याचिकाकर्ता और आगे निवेदन नहीं कर रहे हैं और अनुरोध करते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति का मूल्यांकन दोनों देशों से संचयी आधार पर किया जाना चाहिए ।
45. पूर्व में उत्पादकों द्वारा चीन में संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा था । पाटनरोधी शुल्क के लागू किए जाने के बाद, चीन से आयातों में कुछ हद तक कमी आई है । इससे घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में सुधार हुआ है । तथापि, जर्मनी तथा कोरिया से हुए नए पाटन के कारण, घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन अपनी इष्टतम सीमा तक नहीं पहुंच पाया है । इस तथ्य के मद्देनजर याचिकाकर्ता निवेदन करते हैं कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करते समय पूर्व में अन्य देश से हुए उक्त उत्पाद के पाटन द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा ऐसे स्रोत पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने जैसे तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए ।
46. याचिकाकर्ता कंपनियों में से एक ने अपनी उत्पादन लागत को कम करने के लिए महत्वपूर्ण उत्पादन लागत को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं । ऐसे कदमों से कंपनी की ब्याज देयता में काफी कमी हुई है । परिणामतः इसका असर घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर भी परिलक्षित होता है । तथापि, वर्तमान प्रयोजन के लिए जो बात संगत है वह है विवरणी (ब्याज तथा लाभ की रकम) जिसके लिए घरेलू उद्योग हकदार है, न कि वह स्थिति जिसमें कंपनी का ब्याज अथवा लाभ उच्च हो । उच्च ब्याज लागत वाली कंपनी निम्न लाभ की हकदार होगी जबकि निम्न ब्याज लागत वाली कंपनी उच्च लाभ की हकदार होगी ।
47. संबद्ध देशों से आयातों में समग्र तथा सापेक्ष रूप से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ।
48. संबद्ध वस्तु के कुल आयातों की तुलना में संबद्ध देशों से आयातों के हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ।

49. चीन में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद, उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा बिक्री मात्रा में सुधार हो रहा था । तथापि, जांच अवधि से तत्काल पहले वर्ष की तुलना में जांच अवधि में इनमें गिरावट आई है, यद्यपि चीन में पाटनरोधी शुल्क के लगाए जाने के कारण बिक्री मात्रा में समग्र रूप में आंशिक वृद्धि हुई है ।

50. बिक्री मात्रा में गिरावट के परिणामस्वरूप उत्पादन में गिरावट के बावजूद स्टॉक में वृद्धि हुई है ।

51. घरेलू उद्योग द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रयासों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में कमी आई है । उसी समय, घरेलू उद्योग को बिक्री कीमतें घटाने के लिए मजबूर होना पड़ा है । परिणामतः निम्न स्तर पर ही सही, घरेलू उद्योग को हो रहे वित्तीय घाटे जारी है ।

52. चीन से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग को उच्चतक लाभप्रदता प्राप्त करने की अपेक्षा थी । तथापि चीन से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के साथ-साथ नए स्रोतों से पाटन के कारण घरेलू उद्योग को समुचित लाभ प्राप्ति से वंचित होना पड़ा है ।

53. पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के ऑर्डरों / अनुबंधों से वंचित होना पड़ा है ।

54. आयात इतने निम्न कीमत पर होने के कारण आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत से काफी कम हैं । पाटित आयातों के कारण अत्यधिक कीमत कटौती हो रही है ।

55. पाटित आयातों का पहुंच मूल्य, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम था । यदि आयात कीमतों की मौजूदा प्रवृत्ति जारी रहती है, तो घरेलू उद्योग पर आयातों का अत्यधिक ह्रासकारी / न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा ।

56. यद्यपि उद्योग में कर्मचारियों को उनके पदों पर बनाए रखने की प्रवृत्ति रही है, परंतु पाटित आयातों के कारण उद्योग को अपने रोजगार में कटौती करने पर बाध्य होना पड़ा है ।

57. यद्यपि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है, यह विचारणीय है कि घरेलू उद्योग के रोज़गार स्तर में गिरावट आई है । इस प्रकार, जहां प्रति कर्मचारी रोज़गार में वृद्धि हुई है, जांच अवधि से पूर्व की अवधि की तुलना में जांच अवधि के दौरान प्रति दिन उत्पादन में गिरावट आई है, जबकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसमें वृद्धि होती रही है ।

58. लगाई गई पूंजी पर आय पिछले वर्षों में चीन से पाटन के कारण नकारात्मक रही है और यह प्रवृत्ति जारी है । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई क्षति रहित कीमत पर विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री प्राप्ति निर्धारित क्षति रहित कीमत से कम थी । इससे इस तथ्य को बल मिलता है कि लगाई गई पूंजी पर आय इष्टतम से कम है ।

59. यद्यपि चीन से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के लगाए जाने के कारण पिछले वर्षों में नकद लाभ में सुधार हुआ है फिर भी घरेलू उद्योग को लगातार हो रही हानि के कारण घरेलू उद्योग के नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल असर पड़ा है ।

60. घरेलू उद्योग के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । वास्तव में विकास, सकारात्मक वृद्धि की स्थिति से नकारात्मक स्थिति में पहुंच गया है ।

61. घरेलू उद्योग को नए निवेशों की योजना बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ।

62. यद्यपि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पहले ही अमरीकी डॉलर में पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की है, यह निवेदन किया गया है कि अंतिम शुल्क की सिफारिश भी अमरीकी डॉलर के रूप में की जाए, ताकि विनिमय दर में बदलाव के कारण संरक्षण की मात्रा में कमी न आए । इसलिए, शुल्क केवल संदर्भ कीमत तक ही सीमित रखे जाने चाहिए ।

63. याचिकाकर्ता ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से पहले ही सभी जानकारी उपलब्ध करा दी है । यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी को और अधिक जानकारी / स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है तो याचिकाकर्ता उसे उपलब्ध कराएंगे ।

64. बी ए एस एफ द्वारा प्रस्तुत विभिन्न तर्कों के संबंध में याचिकाकर्ता ने अपने अनुस्मारक में पहले ही विस्तृत ब्यौरा दिया है । यह निवेदन किया जाता है कि, बिक्री मात्रा में गिरावट आने के

बाद भी घरेलू उद्योग को जर्मनी तथा कोरिया से पाटित आयातों के कारण, कीमतों में विशेषकार क्षति हो रही है । 1999-00 में जहां प्रमुखतः चीन से पाटन के कारण गिरावट आई थी, वहीं जांच की अवधि में जर्मनी एवं चीन से पाटित आयातों के कारण बिक्री मात्रा में गिरावट आई है । घरेलू उद्योग की लाभप्रदता अधिकांशतः पुनर्गठित योजनाओं और घरेलू उद्योग द्वारा लागतों को कम और न्यूनतम करने के लगातार प्रयासों से बढ़ी है । तथापि, यदि आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना उत्पादन लागत से की जाए तो यह देखा जाएगा कि उत्पादन लागत आयातों के पहुंच मूल्य से बहुत कम है । इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में भारी कटौती हो रही है । परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग द्वारा बी ए एस एफ को की जाने वाली बिक्रियों में अत्यधिक कमी हुई है । याचिकाकर्ता ने पहले ही उपभोक्ता-वार विवरण प्रस्तुत कर दिया है जिससे यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि घरेलू उद्योग द्वारा बी ए एस एफ को की जाने वाली बिक्रियों में बहुत अधिक कमी हुई है । बी ए एस एफ ने कीमतों को काफी कम किया है और आयातों की कीमतों की बराबरी करने के लिए भारतीय उत्पादकों को संबद्ध वस्तु की कीमतें कम करनी पड़ी हैं । हमने पहले ही व्यापारियों के कुछ पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनसे स्पष्टतया यह सिद्ध होता है कि भारतीय उत्पादकों को बी ए एस एफ को की जाने वाली बिक्रियों को घाटा हुआ है और इन बिक्रियों के संदर्भ में उनके बाजार हिस्से में गिरावट आई है । सर्वसम्मति से आयात, घरेलू खपत का 2.5% है जो कि ई.सी. में कानूनी प्रावधान के अनुसार भी पर्याप्त है ।

65. अंतिम निर्धारण करते समय प्राधिकारी ने क्षति के संबंध में सभी संकेतकों पर विचार किया है । इसमें सभी संगत तथ्य अर्थात् पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में कीमत पर उनका प्रभाव और घरेलू उत्पादकों पर उसका उत्तरवर्ती प्रभाव, उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभप्रदता, निवल बिक्री, प्राप्ति आदि शामिल होंगे । घरेलू उद्योग के लिए समान वस्तु के लिए गैर क्षति कारक कीमत निर्धारित करते समय प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए उत्पादन की इष्टतम लागत पर विचार किया है जिसमें परिकलित सर्वोत्तम खपत मानदंडों और कच्ची सामग्री जिसे जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए उपयोग किया गया है, की वास्तविक कीमत को ध्यान में रखा गया है ।

66. रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों से यह देखा गया है कि संबद्ध देशों में से प्रत्येक का पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के % के रूप में व्यक्त 2% की सीमा से अधिक है । इसके अतिरिक्त, प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा न्यूनतम सीमा से अधिक है । आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करना उचित होगा क्योंकि संबद्ध देशों के निर्यात परस्पर तथा भारतीय बाज़ार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत माल के साथ प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं । अतः प्राधिकारी, संबद्ध देशों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के संचयी मूल्यांकन का प्रस्ताव करते हैं ।

67. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमों के अनुबंध II (iv) के अनुसार ऐसे अन्य संकेतकों पर विचार किया है जो उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन इत्यादि ।

68. निम्नलिखित मापदंडों से यह सिद्ध होता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है :-

	विवरण	इकाई	1999-00	2000-01	अप्रैल, 01-सितंबर, 02	जांच अवधि (वार्षिक)
	बिक्रियां (सूचीबद्ध)		100.00	96.34	142.73	95.15
	उत्पादन लागत (सूचीबद्ध)		100.00	98.43	93.91	93.91
	बिक्री कीमत (सूचीबद्ध)		100.00	100.15	100.16	100.16
	लाभ/हानि (सूचीबद्ध)		-100.00	-73.95	-4.48	-4.48
	उत्पादन	मी.टन	15123	14540	21635	14423
	उत्पादन लागत (सूचीबद्ध)		100.00	96.14	143.06	95.37
	आयात					
	जर्मनी	मी.टन	449	30	714	476
	कोरिया	मी.टन	0	144	338	226
	संबद्ध देशों से कुल आयात	मी.टन	449	174	1052	702
	अन्य देश	मी.टन	2115	1413	1886	1257
	कुल आयात	मी.टन	2564	1587	2938	1959
आयातों में बाज़ार हिस्सा						
	जर्मनी	%	17.51	1.89	24.30	24.30
	कोरिया	%	0.00	9.07	11.50	11.54
	व्यापारिक मांग (सूचीबद्ध)		100.00	104.70	158.22	105.48
	मांग में बाज़ार हिस्सा, घरेलू उद्योग (सूचीबद्ध)		100.00	92.02	90.21	90.21
	अन्य उत्पादक (सूचीबद्ध)		100.00	122.06	121.15	121.15
	संबद्ध देश (सूचीबद्ध)		100.00	37.35	150.60	150.60
	अन्य देश (सूचीबद्ध)		100.00	63.81	56.36	56.35

	उत्पादकता					
	कर्मचारी (सूचीबद्ध)		100.00	95.70	95.53	95.88
	प्रति कर्मचारी उत्पादकता (सूचीबद्ध)		100.00	100.46	149.75	99.47
	क्षमता		171.00	171.00	271.35	180.90
	क्षमता उपयोग		88.44	85.03	79.73	79.73
	नकद घाटा (सूचीबद्ध)		-100.00	-59.43		18.22
वस्तु सूची						
	अधिशेष स्टॉक	मी.टन	849	936	1328	1328
	अधिशेष स्टॉक (सूचीबद्ध)		100.00	90.71	70.48	100.00
रोज़गार						
	कर्मचारी	संख्या	582	557	558	558
	कर्मचारी (सूचीबद्ध)		100.00	95.70	95.88	95.88
उत्पादन की तुलना में आयात						
	संबद्ध देश	%	2.97	1.20	4.86	4.87
	संबद्ध देश (सूचीबद्ध)		100.00	40.31	163.78	163.94
	अन्य देश	%	13.99	9.72	8.72	8.72
	अन्य देश (सूचीबद्ध)		100.00	69.49	62.33	62.32

च. पाटित आयातों की मात्रा और बाज़ार हिस्सा

69. संबद्ध देशों से सोडियम हाइड्रोसल्फाइट के आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यद्यपि आयात बुनियादी तौर पर बहुत से देशों से हो रहे हैं, परन्तु भारत में मांग की तुलना में जांच अवधि के दौरान आयातों में जर्मनी और कोरिया गणराज्य के हिस्से में वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा वर्ष 2000-01 में 37.35% से बढ़कर जांच अवधि (वार्षिक) के दौरान 150.60% हो गया है, जबकि अन्य देशों से आयातों का हिस्सा वर्ष 2000-01 में 63.81% से घट कर जांच अवधि (वार्षिक) के दौरान 56.36% हो गया है। अन्य स्रोतों से भी आयात किए जा रहे हैं परन्तु वे आयात या तो न्यूनतम सीमा से कम हैं अथवा उन पर पाटनरोधी शुल्क लगाया

गया है । संबद्ध देशों से आयातों में तुलनात्मक तथा समग्र दोनों रूपों में वृद्धि हुई है । यह भी स्पष्ट है कि आयातों में घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में और देश में उत्पाद की मांग में आयातों के हिस्से की तुलना में वृद्धि हुई है ।

70. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन तथा क्षमता उपयोग में गिरावट आई है । उत्पादन तथा क्षमता उपयोग में यह गिरावट इस तथ्य के कारण है कि मांग में वृद्धि हुई है । संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की वृद्धि दर संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन और मांग की वृद्धि दर से बहुत अधिक है ।

71. याचिकाकर्ता कंपनियां अपनी कीमतें बाजार स्थितियों के आधार पर निर्धारित करती हैं । बाजार कीमतें पाटित आयातों की कीमतों से प्रभावित थीं क्योंकि पाटित आयातों का हिस्सा वर्ष 2000-2001 में 10.96% से बढ़ कर जांच अवधि (वार्षिक) के दौरान 36.26% हो गया है ।

72. यद्यपि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री मात्राओं में मामूली तौर पर गिरावट आई है, तथापि बिक्री कीमत में मामूली रूप से वृद्धि हुई है । इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग पाटित आयातों की समानता करने के लिए अपनी बिक्री कीमत कम नहीं कर सका । घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और बिक्री कीमत की तुलना में आयातों का पहुंच मूल्य इतना कम है कि घरेलू उद्योग आयातित संबद्ध वस्तु की बराबरी करने के लिए अपनी कीमत कम करने की स्थिति में नहीं है । अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि मौजूदा स्थिति में पाटित आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए घरेलू उद्योग ने अपना लाभ और बाजार दोनों की गंवाया है । सोडिय हाइड्रोसल्फाइट के आयातों में समग्र और प्रतिशत के रूप में वृद्धि के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को बिक्रियों / ठेके का घाटा हुआ है ।

मांग में बाजार हिस्सा

73. मांग में घरेलू उद्योग का हिस्सा वर्ष 2000-2001 में 92.01 से घटकर जांच अवधि (वार्षिक) के दौरान 90.21 हो गया है । अन्य उत्पादकों ने भी मांग में अपना हिस्सा गंवाया है जो संबद्ध देशों के पाटित आयातों को प्राप्त हुआ है । अन्य देशों से आयातों का हिस्सा भी वर्ष 2000-2001 में 63.81 से घटकर जांच अवधि (वार्षिक) के दौरान 53.36 हो गया है ।

साधारण तौर पर मांग 2000-2001 में 104.70 से बढ़कर जांच अवधि (वार्षिक) के दौरान 105.48 हो गई है। अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग में वृद्धि के बाद भी पाटित आयातों ने संबद्ध देशों से सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के बाज़ार हिस्से को विस्थापित कर दिया है।

उत्पादन एवं क्षमता उपयोग

		1999-2000	2000-2001	अप्रैल, 01- सितंबर, 02	जांच अवधि (वार्षिकृत)
		मी. टन	मी. टन	मी. टन	मी. टन
क्षमता	मी. टन	17100	17100	27135	18090
उत्पादन	मी. टन	15123	14540	21635	14423
क्षमता उपयोग	%	88.44	85.03	79.73	79.73
घरेलू बिक्रियां	मी. टन	14468	13939	20650	13767

74. घरेलू उद्योग का सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का उत्पादन 1999-2000 में 15123 मी. टन से घटकर 2000-2001 में 14540 मी. टन हो गया जो आगे जांच अवधि (वार्षिक) के दौरान और घटकर 14423 मी. टन हो गया है। साधारण तौर पर उत्पादन में गिरावट आई है। क्षमता उपयोग में 1999-2000 में 88.44% से 2000-2001 में 85.35% तक तथा अंतिम रूप से जांच अवधि वार्षिकीकृत में 79.73% तक एक स्थिर गिरावट आ रही है।

75. घरेलू उद्योग की बिक्री में 1999-2000 में 14468 मी. टन से 2000-2001 में 13939 मी. टन तक और अंतिम रूप से जांच अवधि वार्षिकीकृत में 13767 मी. टन तक एक स्थिर गिरावट देखी जा सकती है। संबद्ध वस्तुओं के क्षमता उपयोग के साथ-साथ बिक्री मात्रा दोनों में गिरावट की प्रवृत्ति के लिए पाटित आयात सहायक रहे हैं और चूंकि बिक्री मात्रा घट रही है अतः घरेलू उद्योग उत्पादन में वृद्धि करने का इरादा नहीं रखता जिससे भंडार सूची का अतिरिक्त जमाव हो जाएगा।

भंडार सूची तथा संविदाओं के गंवाने का साक्ष्य

76. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भंडार सूची का स्टॉक 2000-2001 में 90.71 से बढ़कर जांच अवधि (वार्षिकीकृत) के दौरान 99.07 हो गया है। प्राधिकारी मानते हैं कि जांच अवधि (वार्षिकीकृत) के दौरान स्टॉक के साथ-साथ बाजार में घरेलू उद्योग के हिस्से के विस्थापन में वृद्धि की प्रवृत्ति का कारण संबद्ध देशों से पाटित आयात हैं। इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि बिक्री मात्रा में गिरावट से स्टॉक में उत्पादन के बावजूद वृद्धि हुई है।

77. यह देखा जा रहा है कि निर्यात कीमत में कमी के कारण घरेलू उद्योग को निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ बिक्री कीमत को संगत बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा और बिक्री कीमत को बाजार में प्रतिस्पर्धा के स्तर पर रखना पड़ा। इस प्रक्रिया में घरेलू उद्योग इसकी सीमान्त लागत वसूल नहीं कर पाया इसलिए घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं को इतनी कम कीमतों पर बेच पाने में असमर्थ रहा जिससे संविदाएं गंवानी पड़ीं। इसलिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटित आयातों के कारण, घरेलू उद्योग को उत्पादों को घाटे पर बेचना पड़ रहा है।

कीमत कटौती, कीमत हास/मंदी और कम कीमत पर बिक्री

78. प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। यह देखा जा रहा है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति पर पाटन का एक पहत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इसके बाजार हिस्से के संरक्षण के लिए, याचिकाकर्ता को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों और कम कीमतों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी थी। इसलिए पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही थी क्योंकि संबद्ध देशों से आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटित आयातों का पहुंच मूल्य, कड़ाई से कीमत कटौती के साक्ष्य का संकेत करता है।

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति के आंकलन के लिए कम कीमत पर बिक्री एक महत्वपूर्ण संकेतक है। प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद की उचित बिक्री कीमत परिकलित की है और इसकी तुलना पहुंच मूल्य से कम कीमत पर बिक्री की सीमा ज्ञात करने के लिए की है। विश्लेषण

से पता चलता है कि कम कीमत पर बिक्री के कहत्वपूर्ण स्तर के प्रभाव के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है । आयातों से घरेलू बाज़ार की कीमतों पर काफी हास / मंदी लाने वाले प्रभाव पड़ रहे थे क्योंकि घरेलू उद्योग पाटित आयातों के मद्देनज़र इसकी बिक्री कीमत को बढ़ाने में असमर्थ था । इसलिए उपलब्ध साक्ष्यों की जांच से यह पता चलता है कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की बिक्री पर घरेलू उद्योग को समग्रतः क्षति उठानी पड़ी । प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री की सीमा निर्धारित की है और उनका यह मानना है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को काफी कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री सहन करनी पड़ी ।

80. घरेलू उद्योग की उचित बिक्री कीमत संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत से कम है और इसके आगे होने वाले आयातों से घरेलू उद्योग की वैध कीमत वृद्धि में बाधा आ रही थी । प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान कीमत हास / मंदी की सीमा निर्धारित की है और नोट किया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को काफी कीमत हास / मंदी का सामना करना पड़ा है ।

रोज़गार

81. घरेलू उद्योग का राजगार स्तर स्थिर रहा है और इसका संकेतक कम या अधिक समान स्तर पर 95 से 96 रहा है । तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रोज़गार के स्तर में इस स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई थी ।

लाभप्रदता

82. उत्पादन की इकाई लागत 1999-2000 में 100 से घटकर 2000-2001 में 98.43 तक और आगे जांच अवधि (वार्षिकीकृत) में घटकर 93.91 हो गई जबकि इकाई बिक्री कीमत मामूली रूप से 1999-2000 में 100 से बढ़कर जांच अवधि (वार्षिकीकृत) के दौरान 100.16 हो गई ।

83. घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में कमी आई है जबकि बिक्री कीमतों में कम होने की प्रवृत्ति नहीं दिखाई दे रही । घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि हो रही है परंतु वित्तीय पुनर्गठन तथा एक याचिकाकर्ता के लाभ के कारण कम लागत की वजह से घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार हुआ है । यह भी पाया गया है कि चीनी आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने पर भी घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं की हानि को पूरा नहीं कर सका जो इस बात का संकेत है कि कथित पाटन के नए स्रोत ही घरेलू उद्योग के हालात सुधारने में बाधक हैं । घरेलू उद्योग ने अपनी वित्तीय स्थिति थोड़ी सी सुधारी है क्योंकि घाटे में वृद्धि हो रही है और अभी भी घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण बिक्री कीमतें कम करने के लिए बाध्य है ।

वृद्धि और निवेश पर आय

84. उत्पाद की मांग बढ़ी है तथापि घरेलू उद्योग की वृद्धि में गिरावट आई है । देश में मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग की वृद्धि में आयातों के कारण बाधा आ रही है । यह नोट किया जाता है कि यदि संबद्ध देशों से पाटित आयातों को रोकने के लिए कोई उपचारात्मक उपाय नहीं अपनाए जाते तो घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण लक्ष्य प्राप्त करने में अथवा बाज़ार से पूंजी उठाने के प्रति सशंकित हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के लिए नए निवेश की योजना बनाना कठिन होगा ।

85. जांच अधीन उत्पाद के लिए जांच अवधि के दौरान निवेश पर आय की दर घरेलू उद्योग के घाटे के कारण नकारात्मक रही है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग इस उत्पाद में नयी पूंजी उठाने में या नए निवेश करने में असमर्थ रहा है ।

86. इसके अतिरिक्त, मज़दूरी में वृद्धि से बिक्री की लागत में अतिरिक्त वृद्धि हुई है जबकि घरेलू उद्योग इसके अपेक्षित लाभों को बनाए नहीं रख सका । प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास देश में प्रचलित विनियमों के तहत मज़दूरी बढ़ाए जाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है । तथापि, बढ़ाई गई मज़दूरी लाभप्रदता को आगे नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी क्योंकि घरेलू उद्योग समानुपातिक रूप से कीमतें बढ़ाने में असमर्थ रहा है ।

87. घरेलू उद्योग की वृद्धि में गिरावट आई है । उत्पादकता में भले ही सुधर आया पर इसने घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधर करने में सहायता नहीं की । तथापि प्राधिकारी नोट करते हैं कि रोज़गार के स्तर में यह स्थिति निश्चित नहीं की जा सकती जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई थी ।

छ. संचयी आकलन

88. . रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों से यह देखा गया है कि संबद्ध देशों में से प्रत्येक का पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के % के रूप में व्यक्त 2% की सीमा से अधिक है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक देश आयातों की मात्रा न्यूनतम सीमा से अधिक है । आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करना उचित होगा क्योंकि संबद्ध देशों के निर्यात परस्पर तथा भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत माल के साथ प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं । वर्तमानप मामलले की स्थिति नियमावली के अनुबंध II में दी गई संचयी मूल्यांकन की सभी शर्तों को पूर्ण करती है, जैसे (1) प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है; (2) प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक है ; तथा (3) आयातित वस्तु, घरेलू वस्तु से सीधे प्रतिस्पर्धा कर रही है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी संगत कारक, संचयी एवं सामूहिक रूप से यह इंगित करते हैं कि जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।

89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विभिन्न घरेलू उत्पादकों के लिए क्षति रहित का मूल्यांकन संबंधित उत्पाद से होने वाली बिक्री वसूली पर उपयुक्त रूप से विचार करके किया गया है । अक्षमताओं को दूर करने के उद्देश्य से प्राधिकारी ने कच्चे माल के प्रयोग, उपयोगिता आदि पर उचित प्रक्रियाओं का मानकीकरण और निर्धारण किया है ।

90. जहां तक भारत में उच्च उत्पादन लागत के कारण हुई क्षति का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत कम शुल्क का नियम है जिसे यहां लागू किया गया है ।

91. इसलिए प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सभी संगत कारक, संचयी एवं सामूहिक रूप से यह दर्शाते हैं कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।

ज. कारणात्मक संबंध

92. यह पता लगाने के लिए क्या घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है, प्राधिकारी ने निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया है :-

93. संबद्ध देशों ने पाटित मूल्यों पर संबद्ध वस्तुओं के प्रचुर आयातों ने घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमतें अलाभकर स्तर तक कम करने के लिए बाध्य किया जिससे भारतीय बाज़ार में कीमत कटौती की स्थिति पैदा हो गई है ।

94. संबद्ध देशों से आयातों ने भारतीय बाज़ार में इस उत्पाद की कीमतों को इतना दबा दिया कि घरेलू उद्योग भारत में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री से अपनी पूरी उत्पादन लागत वसूल करने तथा उचित लाभ अर्जित करने से वंचित हो गया ।

विवरण	1999-00				2000-01				अप्रैल, 01 - सितंबर, 02				जांच अवधि (वार्षिकीकृत)			
	इकाई	मात्रा	मी. टन	मूल्य (लाख)	मात्रा	मी. टन	मूल्य (लाख)	मात्रा	मी. टन	मूल्य (लाख)	मात्रा	मी. टन	मूल्य (लाख)	मात्रा	मी. टन	मूल्य (लाख)
मांग																
आयात	मी. टन	2564			1587			2938			1959					
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी. टन	14468			13939			20650			13767					
कुल मांग	मी. टन	27017			28286			42746			28497					
मांग में हिस्सा																
संबद्ध देश से आयात	%	1066			0.62			2.50			2.50					
अन्य देश	%	7.83			5.00			4.41			4.41					
याचिकाकर्ता	%	53.55			49.28			48.31			48.31					
आयात का हिस्सा																
संबद्ध देशों का हिस्सा		17.51			10.96			36.20			36.20					
अन्य देश		82.49			89.04			63.80			63.80					

95. उपर्युक्त तालिका से यह देखा गया है कि कुल उपभोग में पाटित आयातों की मात्रा का हिस्सा वर्ष 2000-2001 में 0.62% से बढ़कर जांच अवधि में 2.5% हो गया है, जबकि घरेलू उद्योग का बाज़ार हिस्सा वर्ष 1999-2000 में 53.55% से घटकर जांच अवधि में 48.31% रह गया। भारत में पाटित आयात ऐसी कीमत पर आ रहे थे जिससे समान घरेलू उत्पाद की कीमतों में महत्वपूर्ण रूप से कटौती हुई। इस प्रकार पाटित आयातों की कीमतों से समान घरेलू उत्पाद की कीमतों में कमी और मंदी दोनों हुई।

96. मांग में कोई संकुचन नहीं है। इसके अतिरिक्त व्यापार प्रतिबंधक प्रथा या प्रौद्योगिकी विकास जैसा कोई अन्य कारक नहीं है जो घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचा सकता था। भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों में निरपेक्ष रूप से वृद्धि के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप बिक्रियों में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप देश में उत्पाद की मांग में घरेलू उद्योग के हिस्से में और कमी आई। इसके अतिरिक्त आयातों की कम कीमतों ने घरेलू उद्योग को इसकी लाभप्रदता के बारे में आशावादी होने से रोका है।

97. इसलिए प्राधिकारी उपर्युक्त से यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयातों को पहुंचा मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम कीमत पर रहा है। इसके अलावा, भारत में आयात घरेलू उद्योग के लिए गैर क्षतिकारी कीमत से कम कीमत पर किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग एक तर्कसंगत आया अर्जित करने में सक्षम नहीं रहा है। ये मापदंड समग्र और संचयी रूप से इस बात के सूचक हैं कि याचिकाकर्ता ने पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति उठाई है।

झ. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

98. प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का सामान्य तौर पर उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को हटाना है ताकि भारतीय बाज़ार में मुक्त और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनर्स्थापित किया जा सके, जो कि देश के सामान्य हित में है।

99. प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि यद्यपि पाटनरोधी शुल्क संबद्ध वस्तुओं का प्रयोग करके विनिर्मित किए गए उत्पादों की कीमत स्तरों को प्रभावित कर सकते हैं और परिणामस्वरूप इन उत्पादों की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव डाल सकते हैं, तथापि इन पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाज़ार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी । इसके विपरीत पाटनरोधी उपायों से पाटन प्रथाओं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अनुचित लाभ दूर होंगे और घरेलू उद्योग का हास रुकेगा और उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तुओं की व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी ।

100. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों से संबद्ध देशों से आयात भी किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी ।

101. प्राधिकारी ने उचित बिक्री कीमत के संबंध में केवल याचिकाकर्ताओं के निवेदनों पर ही निर्भर नहीं किया है, बल्कि प्राधिकारी ने सोडियम हाइड्रोसल्फाइड की लागत और विनिर्माण प्रक्रिया की मौके पर जांच और सत्यापन के लिए एक टीम को प्रतिनियुक्त किया और भारत में घरेलू उद्योग के लिए पृथक रूप से सोडियम हाइड्रोसल्फाइड की उचित बिक्री कीमत को विस्तृत रूप में निकाला है ।

102. उपभोक्ताओं ने अपने तर्क दिए हैं कि पाटनरोधी उपायों के परिणामस्वरूप कास्टिक सोडा के उपभोक्ताओं के लिए कम प्रतिस्पर्धा और उच्च कीमतों की स्थिति उत्पन्न होगी और यह प्रयोक्ता उद्योग को हानि पहुंचा सकती है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुचित प्रथाओं पर आधारित कीमत फायदे अन्यायपूर्ण हैं और अंत में उपभोक्ता के हित के लिए भी हानिकारक हैं ।

ज. निष्कर्ष

103. पूर्वोक्त पर विचार करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि :

- (i) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का भारत को निर्यात इनके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है ;
- (ii) भारतीय उद्योग ने वास्तविक क्षति उठाई है ;

(iii) यह क्षति संचयी रूप से संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है ।

104. प्राधिकारी घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को हटाने के लिए संबद्ध देशों से सोडियम हाइड्रोसल्फाइट के सभी आयातों पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक समझते हैं । प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए पाटन मार्जिन को उपर्युक्त पैराग्राफों में दिखाया गया है । प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क की राशि को पाटन मार्जिन के समान या कम होने की सिफारिश करते हैं, जिसे यदि लगाया जाता है तो यह घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करेगी । क्षति का निर्धारण करने के उद्देश्य से आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना जांच अवधि के लिए निर्धारित याचिकाकर्ता कंपनियों की भारित औसत गैर-क्षतिकारी कीमत से की गई है ।

105. तदनुसार, प्राधिकारी सिफारिश करते हैं कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित सीमाशुल्क शीर्ष 2831.10 के अंतर्गत आने वाली विचाराधीन संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा पाटनरोधी शुल्क, जैसा नीचे निर्दिष्ट है, लगाया जाए । यह पाटनरोधी शुल्क निम्नलिखित तालिका के कॉलम सं. 9 में उल्लिखित राशि और नीचे उल्लिखित संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ के अध्याय 28 के अंतर्गत आने वाली संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर प्रति मी. टन अमरीकी आयातों के पहुंच मूल्य का अंतर होगा ।

36

क्र. सं.	उपशीर्ष	उत्पाद विवरण	विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	2831.10	सोडियम हाइड्रोसल्फाइड		जर्मनी	कोरिया आर. पी. के अलावा कोई देश	मै. बी. ए. एस. एफ जर्मनी	मै. बी. ए. एस. एफ जर्मनी	1034.76	मीट्रिक टन	अमरीकी डॉलर
2	2831.10	सोडियम हाइड्रोसल्फाइड		जर्मनी	कोरिया आर. पी. के अलावा कोई देश	मै. बी. ए. एस. एफ जर्मनी	कोई निर्यातक	1034.76	मीट्रिक टन	अमरीकी डॉलर
3	2831.10	सोडियम हाइड्रोसल्फाइड		जर्मनी	कोरिया आर. पी. के अलावा कोई देश	कोई उत्पादक	मै. बी. ए. एस. एफ जर्मनी	1034.76	मीट्रिक टन	अमरीकी डॉलर
4	2831.10	सोडियम हाइड्रोसल्फाइड		जर्मनी के अलावा कोई देश	जर्मनी	मै. बी. ए. एस. एफ जर्मनी के अलावा कोई उत्पादक	मै. बी. ए. एस. एफ जर्मनी के अलावा कोई निर्यातक	1034.76	मीट्रिक टन	अमरीकी डॉलर
5	2831.10	सोडियम हाइड्रोसल्फाइड		जर्मनी	कोरिया आर. पी. के अलावा कोई देश	मै. बी. ए. एस. एफ जर्मनी के अलावा कोई उत्पादक	मै. बी. ए. एस. एफ जर्मनी के अलावा कोई निर्यातक	1034.76	मीट्रिक टन	अमरीकी डॉलर
6	2831.10	सोडियम हाइड्रोसल्फाइड		कोरिया आर. पी. के अलावा कोई देश	जर्मनी के अलावा कोई देश	कोई उत्पादक	कोई निर्यातक	1034.76	मीट्रिक टन	अमरीकी डॉलर
7	2831.10	सोडियम हाइड्रोसल्फाइड		कोरिया आर. पी. के अलावा कोई देश	कोरिया आर. पी. के अलावा कोई देश	कोई उत्पादक	कोई निर्यातक	1034.76	मीट्रिक टन	अमरीकी डॉलर

106. इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथा निर्धारित होगा और उसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 तथा 9क के अंतर्गत आने वाले शुल्कों को छोड़कर सभी सीमाशुल्कों के आंकलन योग्य मूल्य शामिल होंगे ।

107. उपर्युक्त के अधीन, प्राधिकारी दिनांक 25 फरवरी 2003 के प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं ।

108. इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी ।

एल. बी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2003

FINAL FINDINGS

Subject : Anti-dumping investigation concerning import of Sodium Hydrosulphite originating in or exported from Germany and Korea RP.

No. 14/34/2002-DGAD - Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof;

A. PROCEDURE

1. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
 - i) The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the above Rules, received a petition filed by M/s Transpek Silox Industry Ltd., Vadodara and M/s. Demosha Chemicals Pvt. Ltd., Mumbai, (hereinafter referred to as Petitioners) on behalf of the domestic industry, alleged dumping of Sodium Hydrosulphite originating in or exported from Germany and Korea RP (hereinafter referred to as subject countries).
 - ii) The Authority issued a public notice dated 14.11.2002 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping investigations concerning imports of the subject goods classified under chapter 28 and 29 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975 originating in or exported from Germany and Korea RP.

- iii) The Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) notified preliminary findings vide Notification No. 14/34/2002-DGAD dated the 25th February, 2003 with regard to Anti Dumping investigations concerning imports of Sodium Hydrosulphite originating in or exported from Germany and Korea RP and requested the interested parties to make their views known in writing within forty days from the date of its publication;
- iv) The Authority forwarded a copy of the Preliminary Findings to known interested parties, who were requested to furnish their views, if any, on the Preliminary Findings within forty days of the date of the letter;
- v) The Authority also forwarded copy of the Preliminary Findings to the Embassies/High Commissions/Representatives of subject countries in New Delhi with a request to furnish their views on the Preliminary Findings;
- vi) The Authority held a public hearing on **5th May 2003** to hear the interested parties orally, which was attended by representatives of the domestic industry, importers and exporters from subject countries. The parties attending the public hearing were requested to file written submissions of views expressed orally. The written submissions thus received from interested parties have been considered by Designated Authority in these finding;
- vii) The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7);
- viii) The cost of production of the domestic industry was also analysed to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) based on the information furnished by petitioner so as to ascertain if anti dumping duty lower than dumping margin would be sufficient to remove injury to domestic industry. The cost of production data of the following companies were considered and examined appropriately:--

1. M/s Transpeak Silox Industry Ltd., Vadodara
 2. M/s. Demosha Chemicals Pvt. Ltd., Mumbai
- ix) The Authority conducted on-the-spot verification of the domestic industry to the extent considered necessary;
- x) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties and comments received on the same have also been duly considered in these findings;
- xi) Investigation was carried out for the period starting from 1st April 2001 to 30th September 2002 i.e. the period of investigation (POI).
- xii) ****In this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION /LIKE ARTICLE

VIEWS OF DOMESTIC INDUSTRY

2. The product under consideration is known as Sodium Hydrosulphite. It is a white or greyish crystalline powder, free from visible foreign particles with pungent odour. It has been imported under Chapter 28 and 29 of Customs Tariff Act.

3. As far as the process of manufacturing is concerned, the petitioners adopt both the Zinc and Formate route for producing the subject goods. This is internationally acceptable and adopted by manufacturers worldwide. Amalgam process adopted by M/s BASF is, in fact, being phased out considering the usage of Mercury in the process. However, whatever is the technology, the end product is comparable and technically & commercially substitutable.

4. The exporter has claimed that their product is preferred over Indian product. Petitioners submit that (a) this is a mere statement, factually incorrect; (b) the exporter has not been exporting large volumes for a long period and, therefore, question of preference does not arise; (c) preference was non existence, when imports were being made from China; (d) increase in imports, is due to reduction in prices; (e) it is the price offered by BASF and not preference of the customers which is the

real reason, as can be seen from the statement of customer wise sales statement; and (f) preference of one product over other product implies that the two are like articles.

VIEWS OF M/S BASF

5. There are two different Production Processes worldwide. BASF manufactures Sodium Hydroxide by Amalgam Process. Our "Hydrosulfit N" brand contains a dust-binding agent, which is completely soluble in water, That is why it commands preferences over locally manufactured product. The locally manufactured product contains a mineral oil as a dust-binding agent and is not completely soluble in water.

6. In the Publication of Harriman Chemsult it is written, that DEMOSHA is using Zinc process and second petitioner SILOEX uses both Zinc and Formate process. The statement that the technology adapted by the Indian Industries is comparable with the Manufactures of Sodium Hydrosulphite in Germany and Korea RP is completely wrong and misleading.

EXAMINATION OF THE AUTHORITY

7. The product under consideration is known as Sodium Hydrosulphite (Also referred to as subject goods hereinafter). It is a white or grayish crystalline powder, free from visible foreign particles with pungent odour. It has been imported under Chapter 28 and 29 of Customs Tariff Act. Though the classifications sub-headings 2831.1001 and 2832.1002 suggest description as Sodium Hydrosulphite but correct Custom classification may be treated under 6 digit heading 2831.10 as Sodium Sulphites. The classification is, however indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation. The Authority notes that the investigation covers all forms of Sodium Hydrosulphite as product under consideration

8. There is no significant difference in Sodium Hydrosulphite produced by the Indian industry and Sodium Hydrosulphite exported from Germany and Korea, which can have an impact on price. Sodium Hydrosulphite produced by the Indian industry and imported from Germany and Korea are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used

the two interchangeably. Sodium Hydrosulphite produced by the petitioners and imported from Germany and Korea should be treated as like articles in accordance with the anti dumping Rules. The technology adopted by the Indian industry is comparable with the technology adopted by the manufacturers of Sodium Hydrosulphite in Germany and Korea.

9. The Authority, therefore, notes that the goods produced by the Domestic Industry and those exported from the subject countries are like article within the meaning of the Rules 2(d).

C. DOMESTIC INDUSTRY:

10. As per Rule 2(b) of the Anti Dumping Rules, "domestic industry means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry." Further Rule 5(3) of the Anti Dumping Rules states that Designated Authority shall not initiate any investigations pursuant to an application made under sub rule (1) unless it determines on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to the application expressed by domestic producers of the like product that the application has been made by or on behalf of the Domestic Industry provided that no investigation shall be initiated if domestic producers expressly supporting the application account for less than 25% of the total production of the like article by the Domestic Industry .

11. M/s. Transpeak Silox Industry Ltd., and M/s. Demosha Chemicals Pvt. Ltd. have filed the petition, on behalf of the domestic industry. These petitioner companies represent 54.80% of the subject goods under production.

12. The Authority notes that the domestic producers constitute more than 50% of the total domestic production and there is no opposition to the petition by any of the domestic producers, therefore, have the standing to file the petition on behalf of the domestic industry as per Rule 5 (3) (a) and (b) of the Anti-Dumping Rules and also represent Domestic Industry in terms of Rule 2(b)

VIEWS OF EUROPEAN UNION

13. The European Commission finds that the preliminary findings do not satisfy the requirements spelt out in the WTO Anti-Dumping Agreement, in particular Article 2 on dumping and Articles 3.4 and 3.5 on injury. The DA has failed to demonstrate the existence of dumping, has neglected to examine all relevant economic factors and has not provided any evidence on the existence of a causal link between the alleged dumped imports and material injury to the domestic industry. Finally, the European Commission finds that DA has omitted to adequately address the existence of other factors and their impact on the alleged injury.

14. The European Commission is surprised to note that the DA has entirely failed to account for the significant remaining domestic sales (of the non complaining industry), which on average represent 40% of total domestic consumption. In order to give a fair and complete view of the situation in the domestic industry, the trends in sales and market shares of the remaining domestic producers should have been examined.

15. The Commission would like to point to the fact that the market share of the petitioner has fallen by 5.24 percentage points from 1999/00 to IP, whereas that of the alleged dumped imports in the same period has increased by only 0.84 percentage points. This leaves a total of 4.41 percentage points accounted for. It would appear that the petitioner's loss of market share has been brought about by intra-industry competition and not by alleged dumped imports, which would effectively break any causal link between dumped imports and injury.

EXAMINATION OF THE AUTHORITY

16. The Authority has determined separate dumping margins for both cooperating and non-cooperating exporters. Since the Indian anti-dumping rules provide lesser duty, and merely because the dumping margin is different for cooperative and non cooperative exporter, so the benchmark can still be the same for both.

17. As regards the examination of factors of injury under Article 3.4 and Article 3.5, the Authority examined various injury parameters relating to the domestic industry on the basis of their costing and financial information. With regard to improvement in some parameter, it would be relevant to point out that improvement in few parameters do not imply that the domestic industry has not suffered material injury. Even one single parameter may be sufficient to establish that the domestic industry

has suffered material injury. With regard to market share in demand, it is noted that the petitioner companies constitute more than 50% of the domestic production with complete costing information.. The injury parameters have been examined in detail in a separate section on Injury and Causal Link of these findings.

18. The Authority also notes that there is no reason for concern that injury to the domestic industry could have been due to other Indian producers. On the contrary, there is positive evidence that the domestic industry has lost market due to dumped imports, prices have declined due to steep decline in the import prices and adverse performance of the domestic industry is due to dumped imports. Since Indian Anti-dumping Rules provide for lesser duty Rule, any such impact due to higher cost of production is automatically restricted

D. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN:

19. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:-

- (i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
- (ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either: -
 - (a) Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - (b) The cost of production of the same article in the country of origin along with reasonable addition for - administrative, selling and general costs and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

VIEWS OF DOMESTIC INDUSTRY

20. Designated Authority sent questionnaire to known exporters/producers in Germany and Korea and Embassy of the subject countries in India. However only M/s. BASF from Germany responded to the Authority. The response filed by the exporter was grossly deficient and inadequate as is evident from the preliminary findings itself. It is not clear from the disclosure statement that whether the exporter has furnished profit & loss account for the period of investigation. Further, in the preliminary finding, it is admitted that the exporter had not furnished cost of production of the subject goods. It is not clear from disclosure statement that whether the exporter has furnished cost of production and whether the cost information furnished is for period of investigation.

21. With regard to Korea RP, there is no response from Korea. Thus, the claim of the domestic industry earlier in the petition and the preliminary findings notified by the Designated Authority now remains unrefuted. Such being the case, petitioners request the Designated Authority to kindly confirm the preliminary findings.

22. Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

23. The Authority provided opportunity to the exporters from subject countries to furnish information relevant to the investigations and offer comments, if any, in accordance with the Section cited above. The Authority wrote to the Embassies/High Commissions/Representative of subject countries in India also. The Authority sent questionnaires to all the known exporters for the purpose of determination of export price and normal value in accordance with Section 9A(1) (c) of the Custom Tariff Act Only M/s. Solvay Belgium filed the response which were incomplete. None of the exporters responded to the preliminary findings and did not offer comment either on dumping or injury.

VIEWS OF EXPORTER (M/s. BASF GERMANY)

24. The exporter claimed adjustment on account of selling & marketing costs but no justification was provided for such claim and hence such unsubstantiated claims were rejected. As per Para 2 of Annexure 1 of the Rules the domestic sales of the product under consideration were compared with the cost of production plus selling administrative and general costs which were provided separately for exports, domestic sales and exports to third countries.

Although the Hon'ble Authority in its statement has mentioned that domestic sales of the product under consideration were compared with the cost of production plus selling administrative and general costs which were provided separately for exports, domestic sales and exports to third countries but adjustments on account of selling and distribution costs towards domestic sales have not been allowed.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY**Germany****M/s. BASF, Germany**

25. M/s. BASF maintains Audited Accounts and calendar year is the accounting year for the company. The complete BASF accounts are kept in Euro currency. The company maintains its accounts on SAP. Different products are considered as separate product centers and profitability is assessed separately for each product. Although the period of investigation was different from the accounting year kept by the exporter, still it was possible to obtain the cost of production of the subject goods for the period of investigation from the SAP.

NORMAL VALUE:

26. The company has furnished transaction wise details of sale made in the home market of Sodium Hydrosulphite for the period of investigation. The information was verified with the basic records of sales and invoices and found to be correct. The company has sold 4263 Mt of Sodium Hydrosulphite in the domestic market during the period of investigation. It was further observed that all the domestic sales were made at cif level. In order to assess the sale at ex factory level, the exporter has claimed certain adjustments in these sales transactions. The exporters claim of adjustment on account of selling & marketing

costs was not considered as it was neither justified nor substantiated with facts during the course of on-spot verification, hence, such unsubstantiated claims were rejected by the Authority for the purpose of arriving at ex-factory cost of domestic sales in their home market. As per Para 2 of Annexure I of Rules the domestic sales of the product under consideration were compared with the cost of production plus selling administrative and general costs which were provided separately for exports to India, domestic sales, and exports to third countries. The domestic sales in the domestic market are found to be in the ordinary course of trade. The company provided copies of profit and loss account and balance sheet for the current year and previous two financial years showing the determination of gross profit, details of selling and administration and other costs and net profit. The cost of production was determined and compared with the domestic sales and it is found that all sales transaction are above the cost of production and were therefore in the ordinary course of trade. The normal value has therefore been based on the average sales realization of the subject goods in the domestic market. Adjustments on account of packing, freight, storage and handling have been considered to arrive at the ex factory domestic sales price.

27. The Authority has arrived at the Normal Value for M/S BASF, Germany as ****\$/MT.

EXPORT PRICE:

28. The exporter has furnished invoice wise details of exports made to India during the period of investigation. The information submitted was verified with the basic records and invoices. The exporter in its response to the questionnaire and subsequent clarification was submitted that the exports to India are in Euro. However during the course of verification it was observed that the exports are made in US\$, and the exporter submitted revised information in Appendix 2 of the questionnaire. M/s BASF has sold 840 Mt of subject goods to India during the period of investigation. Sales to India are directly shipped from M/S BASF, Ludwigshafen, Germany to the Indian customer. It was also observed during the course of verification that the product under consideration was delivered /sold only to M/s Ramanand Kidernath International in India by the exporter during the period of investigation. Invoicing is done by BSEA, Singapore. For acquiring the customers BASF India gets a commission of 3%. BSEA, Singapore gets a commission of 3.5% for invoicing, handling of receivables, order processing etc. The exporter has claimed adjustments on account of such commissions to its sister

concerns at Singapore and India. It was observed that the sales were made at CIF level and adjustments claimed on account of inland freight, handling charges etc., was verified from their system and found to be in order.

29. The Authority, therefore, determined the ex-factory export price for M/S BASF Germany as US\$ ****/MT.

Other Exporters/Producers from Germany

Normal Value

30. The Authority notes that none of the exporters from Germany except M/s. BASF responded. The Authority in view of non-cooperation, has constructed the normal value for all other producers/exporters on the basis of estimated costs available for cooperative exporters and facts available in accordance with Rule 6 (8) of anti dumping Rules.

31. The normal value is therefore referenced as ****\$/MT.

Export Price

32. The Authority notes that the export price has been determined on the basis of the statistical information from DGCI&S Kolkata. The adjustments on ocean freight, ocean insurance, commission, inland freight and port expenses to an extent of ****\$/MT, ****\$/MT, ****\$/MT, ****\$/MT, and ****\$/MT respectively have been estimated from the adjustments of the cooperative exporters/producers from Germany.

33. The ex-factory export price is referenced as ****\$/MT.

Korea, RP

Normal Value

34. The Authority notes that none of the exporters from Korea has responded by way of questionnaire response to the initiation notification or subsequent to the preliminary findings. The Authority in view of non-cooperation, constructed the normal value for all producers/exporters on the basis of facts available as per Rule 6 (8) of anti dumping Rules. Thus the constructed cost of production with due adjustments has therefore been referenced for the purpose of determination of normal value of the subject goods in Korea.

35. The normal value is therefore referenced as ****\$/MT.

Export Price

36. The Authority notes that the export price has been determined on the basis of the data from DGCI&S Kolkata. Since there is no response from exporters, adjustments on ocean freight, ocean insurance, commission, inland freight, and port expenses to an extent of ****\$/MT, ****\$/MT, ****\$/MT, and ****\$/MT have respectively considered as provided by the petitioners.

37. The ex-factory export price is referenced as ****\$/MT.

DUMPING-Comparison of Normal Value & Export Price

38. The rules relating to comparison provides as follows:

39. "While arriving at margin of dumping, the Designated Authority shall make a fair comparison between the export price and the normal value. The comparison shall be made at the same level of trade, normally at ex-works level, and in respect of sales made at as nearly possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are demonstrated to affect price comparability."

40. The Authority has followed the consistent policy of adopting the principles governing the determination of Normal Value, Export Price and Margin of Dumping as laid down in Annexure I of the Anti Dumping Rules. Based on the Normal values and Export prices as indicated above the Authority assessed the Dumping Margins in case of all exporters/Producers from the subject countries as given in the table below:-

The dumping margin for exporter/producers comes as under:

Exporter/Producer	Normal Value (NV) US\$/MT	Export Price (EP) US\$/MT	Dumping Margin as % of EP
Germany			
(i) M/s. BASF	****	****	22.97%
(ii) All other exporters/producers	****	****	35.55%

Korea RP			
(i) exporters/producers	All ****	****	98.01%

The above Dumping Margins are above the de-minimus limits.

E. INJURY AND CAUSAL LINK:

41. The principles for determination of injury set out in Annexure-II of the Anti-Dumping Rules lay down that:

- i. A determination of injury shall involve an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products.
- ii. While examination the volume of dumped imports, the said Authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of Rule 19 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilisation, sales quantum, stock, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping, etc. in accordance with Annexure II(iv) of the rules supra.

CUMULATIVE ASSESSMENT OF INJURY:

42. Annexure II (iii) under Rule 11 supra further provides that "in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to Anti Dumping investigation, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, only when it determines that the margin of dumping

established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the imports of the like article or where the export of the individual country is less than three percent, the imports cumulatively accounts for more than seven percent of the imports of like article, and cumulative assessment of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles”.

VIEWS OF M/S BASF:

43. The data presented does not sufficiently support the claim of Material Injury as per following analysis:

- (i) Domestic sales only decreased by 4.63% from 1999-2000 to POI and by 1.23% from 2000-01 to POI.
- (ii) Production cost per unit declined from 100 (1999-2000) to 98.43 (2000-01) to 93.31 (POI).
- (iii) Where as profitability has increased over the same period from 100 (1999-2000) to 100.14 (2000-01) to 100.16 (POI).
- (iv) How alleged dumped imports, which represent only 2.5% of total domestic consumption, could have had significant impact on the Petitioners, which account for 48% of domestic consumption.
- (v) The trend in sales and market share of the remaining domestic Industry, which on average represent 40% of total consumption should also be kindly, examine.
- (vi) The market share of the Petitioners has fallen by 5.24% from 1999-2000 to POI where alleged imports have increased by only 0.84%. These leaves a total 4.41% unaccounted for. It would appear that the Petitioners' loss of market share has been brought down by INTRA-INDUSTRY completion.

VIEWS OF DOMESTIC INDUSTRY:

44. The parameters for cumulative assessment are well satisfied in this case. Any interested party has not disputed this. Therefore, petitioners refrain from making any further submissions and submit that the injury to the domestic industry is required to be assessed cumulatively from the two countries.

45. The subject goods were earlier being dumped by the producers in China. With the imposition of anti dumping duty, the imports from China have been limited to an extent. This has helped the domestic industry in

improving its performance. However, the performance of the domestic industry could not reach optimal levels due to fresh dumping experienced from Germany and Korea. In view of the same, petitioners submit that the fact of previous dumping of the product from a different country causing injury to the domestic industry and imposition of anti dumping duty on such source may kindly be kept in mind while assessing the performance of the domestic industry.

46. One of the petitioner companies has taken significant steps in reducing its cost of production. There is a significant reduction in the interest liability of the Company due to such steps. This has consequently reflected in the profitability of the domestic industry. However, what is relevant for the present purpose is the return (sum of interest and profit) which the domestic industry is entitled, rather than when the Company has higher of interest or higher of profits. A Company having higher interest cost would be entitled to lower profits while a Company with lower interest cost would be entitled to higher profits.

47. The imports from subject countries have increased significantly both in absolute and relative terms.

48. Share of imports from the subject countries has increased significantly in relation to total imports of subject goods.

49. Production, capacity utilization and sales volumes were improving with the imposition of anti dumping duty on China. However, the same has declined in Period of Investigation as compared to immediate preceding year, even though the sales volumes in overall terms have partially increased due to imposition of anti dumping duty on China.

50. Decline in sales volumes has resulted in increase in stocks in spite of decline in production.

51. The cost of production of domestic industry has declined as a result of continuous dedicated efforts of the domestic industry. At the same time, the domestic industry has been forced to reduce the selling price. Resultantly, domestic industry continues to make financial losses, albeit at a lower level.

52. The domestic industry had expected to achieve optimum profitability after imposition of anti dumping duty on imports from China. However, dumping from new sources with the imposition of antidumping

duty on imports from China has prevented the domestic industry from realizing reasonable profits.

53. The domestic industry has lost orders/contracts due to dumped imports.

54. The imports were at so significantly low prices that the landed price of imports is significantly below the average selling price of the domestic industry. Dumped imports are causing severe price undercutting.

55. Landed value of the dumped imports was below the cost of production of the domestic industry. Should the present trend of import prices continue, the imports would have severe suppressing/depressing effect on the domestic industry.

56. Though the industry has a tendency to retain its employees, the dumped imports have forced the industry to curtail its employment.

57. Though the productivity of the domestic industry has been increase, it is to be considered that the employment level of the domestic industry has declined. Thus, while production per employee has increased, Production per day declined in POI as compared to previous period, even though the same had been increasing over the years.

58. Return on capital employed has been negative in previous years due to dumping from China and that trend continues. Considering the non-injurious price determined by the Designated Authority, it can be said that the sales realization of the domestic industry was lower than the non-injurious price determined. This further established that the return on capital employed has been sub-optimal.

59. Cash flow of the domestic industry has been adversely affected by the continuous losses being suffered by domestic industry, even though cash profits over the years have been improving with the imposition of anti dumping duty on imports from China.

60. Growth of the domestic industry is adversely affected. In fact, growth has become negative from a situation of positive growth.

61. The domestic industry is finding it difficult to plan fresh investments.

62. Though the Designated Authority has already recommended anti-dumping duty in terms of US \$, it is submitted that the final duties may also be recommended in terms of US \$ only, so that erosion in the quantum of protection does not take place on account of changes in the exchange rate. However, the duties may please be kept in terms of reference price only.

63. Petitioners have earlier provided all information for the purpose of the present investigation. Should the Designated Authority require any further information/clarification, petitioners shall be pleased to provide the same.

64. With regard to various arguments presented by BASF, petitioners have already given detailed comments in their rejoinder. It is submitted that the domestic industry is suffering injury more on price front due to dumped imports from Germany and Korea, even though the sales volumes have also declined. While decline in 1999-00 was predominantly due to dumping from China, the dumped imports from Germany and Korea have resulted in decline in sales volumes in POI. Profitability of the domestic industry has improved more because of restructuring plans and continuous efforts to curtail and marginalise costs by the domestic industry. However, should the landed price of imports be compared with the cost of production, it would be seen that the same is significantly below the landed price of imports. Further, imports from subject countries are significantly undercutting the prices of domestic industry. Resultantly, the domestic industry has lost significant sales to BASF. Petitioners have already provided customer wise sales statement, which clearly establishes that the domestic industry has lost sales to BASF. BASF has reduced the prices considerably and Indian producers are being forced to reduce the prices of subject goods so as to match the prices of imports. We have already provided some letters from dealers which clearly establishes that Indian producers have lost sales to BASF and their market share in respect of these sales has declined. Imports admittedly represented 2.5% of domestic consumption, which is significant, even going by the legal provision in the EC.

EXAMINATION OF THE AUTHORITY:

65. The Authority has taken into account all indices regarding injury while doing the final determination. This would involve all relevant facts viz., volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market and its subsequent effect on domestic producers, production,

capacity utilisation, profitability, net sales realisation etc. While determining the non-injurious price for the like article for the domestic industry, the Authority considered the optimum cost of production for the domestic industry which would take into account the normated best consumption norms and would also take into account the actual price of the raw materials during the period of investigation which go into the production of the product under consideration.

66. It is observed from the facts available on record that the margins of dumping from each of the subject countries are more than the 2% limit expressed as % of export price. Also the volumes of imports from each of the country are more than de minimus. Cumulative assessment of the effects of imports would be appropriate since the exports from the subject countries directly compete with each other and with the goods offered by the domestic industry in the Indian market. The Authority, therefore, proposes to assess injury to the domestic industry from the subject countries cumulatively.

67. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilisation, sales quantum, stock, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping, etc. in accordance with Annexure II(iv) of the rules supra.

68. Following parameters establish that material injury has been caused to the domestic industry from dumped imports from the subject countries;

Particulars	Unit	1999-00	2000-01	Apr. 01-Sept. 02	POI (annualized)
Sales (indexed)		100.00	96.34	142.73	95.15
Cost of Production (indexed)		100.00	98.43	93.91	93.91
Selling Price (indexed)		100.00	100.15	100.16	100.16
Profit/Loss (indexed)		-100.00	-73.95	-4.48	-4.48
Production	MT	15123	14540	21635	14423
Production (indexed)		100.00	96.14	143.06	95.37
Imports					
Germany	MT	449	30	714	476
Korea	MT	0	144	338	226
Total imports from subject countries	MT	449	174	1052	702
Other countries	MT	2115	1413	1886	1257

	Total imports	MT	2564	1587	2938	1959
Market share in imports						
	Germany	%	17.51	1.89	24.30	24.30
	Korea	%	0.00	9.07	11.50	11.54
	Merchant demand (indexed)		100.00	104.70	158.22	105.48
	Market share in demand, Domestic Industry (indexed)		100.00	92.02	90.21	90.21
	Other Producers (indexed)		100.00	122.06	121.15	121.15
	Subject countries (indexed)		100.00	37.35	150.60	150.60
	Other countries (indexed)		100.00	63.81	56.36	56.35
Productivity						
	Employees (indexed)		100.00	95.70	95.53	95.88
	Productivity per employees (indexed)		100.00	100.46	149.75	99.47
	Capacity		171.00	171.00	271.35	180.90
	Capacity Utilization		88.44	85.03	79.73	79.73
	Cash loss (indexed)		-100.00	-59.43		18.22
Inventories						
	Closing stocks	MT	849	936	1328	1328
	Closing Stocks (indexed)		100.00	90.71	70.48	100.00
Employment						
	Employees	Nos.	582	557	558	558
	Employees (indexed)		100.00	95.70	95.88	95.88
Imports in Relation to Production						
	Subject countries	%	2.97	1.20	4.86	4.87
	Subject countries (indexed)		100.00	40.31	163.78	163.94
	Other countries	%	13.99	9.72	8.72	8.72s
	Other countries (indexed)		100.00	69.49	62.33	62.32

F. Volume and Market share of dumped imports

69. Imports of Sodium Hydrosulphite from subject countries have increased significantly. While the imports are primarily from many countries, but share of imports from Germany and Korea RP have increased during the period of investigation in relation to the demand in India. The share of imports from subject countries has increased from 37.35% in 2000-2001 to 150.60% during the POI (annualized), whereas the share of imports from other countries has decreased from 63.81% in 2000-2001 to 56.36% during the POI (annualized). Imports are coming from other sources also but those imports are either di-minimus or attracting anti-dumping duty. Imports from subject countries have increased both in relative and absolute terms. It is also evident that the imports are increased in relation to production of the domestic industry and share of imports in demand of the product in the country. .

70. The production and capacity utilization of the domestic industry has decreased during the period of investigation. This decrease in the production and capacity utilization is due to the fact that demand has increased. The rate of growth of imports of subject goods is much more than the rate of growth of domestic production and demand of subject goods.

71. The petitioner companies determine their prices based on prevailing market conditions. The market prices were driven by the prices of the dumped imports as the share of dumped imports has increased from 10.96 % in 2000-2001 to 36.26% during the POI (annualised).

72. Though domestic sales volumes of the domestic industry have marginally decreased, the selling price has marginally improved. Further, domestic industry could not reduce its selling price to match dumped imports. The landed price of imports is so low compared to the cost of production and selling price of the domestic industry that the domestic industry is not in a position to reduce its price to match with the price of imported subject goods. The Authority, therefore, notes that in this prevailing situation the domestic industry lost both the profit and the market to compete with the dumped imports. The increase of imports both in absolute terms as well as percentage terms of Sodium Hydrosulphite has led to the loss of sales/contract to the domestic industry.

Market share in demand

73. The share of domestic industry in demand has decreased from 92.01 in 2000-2001 to 90.21 during the POI (annualised). The other producers have also lost their share in demand, which have been taken by the dumped imports from subject countries. The share of imports from other countries has also decreased from 63.81 in 2000-2001 to 56.36 during the POI (annualised). The demand in general has increased from 104.70 in 2000-2001 to 105.48 during the POI (annualised). The Authority, therefore, notes that the dumped imports have displaced the market share of domestic industry even after increase in demand because of dumped imports of sodium hydrosulphide from subject countries.

Production & Capacity Utilisation

		1999-2000	2000-2001	Apr,01-Sept,02	POI (ANNUALISED)
		MT	MT	MT	MT
Capacity	MT	17100	17100	27135	18090
Production	MT	15123	14540	21635	14423
Capacity Utilisation	%	88.44	85.03	79.73	79.73
Domestic sales	MT	14468	13939	20650	13767

74. The production of Sodium Hydrosulphite by the domestic industry has decreased from 15123 MT in 1999-2000 to 14540 MT in 2000-2001, which has further decreased to 14423 MT during the POI (Annualised). In general production has declined. There has been a consistent decline in the capacity utilisation from 88.44% in 1999-2000 to 85.35% in 2000-2001 and finally 79.73% in POI annualised.

75. Sales of the domestic industry showing a consistent decline from 14468 MT in 1999-2000 to 13939 MT in 2000-2001 finally to 13767 MT during the annualised POI. The dumped imports are instrumental for a declining trend both in capacity utilisation as well as in the sales volume of the subject goods respectively, and since the sales volumes is declining, the domestic industry does not intend to increase the production which will lead to further stocks of inventory.

Inventory and evidence of loss of contract

76. The Authority notes that the inventory stocks have increased from 90.71 in 2000-2001 to 99.07 during the POI (annualised). The Authority holds that the increasing trend in stocks along with the displacement of share of domestic industry in the market during the POI (annualised) is due to the dumped imports from the subject countries. The Authority, therefore, notes that the declining sales volume has resulted in increase in stocks in spite of decline in production.

77. It has been observed that because of the decline in export price, the domestic industry is forced to match the selling price with the landed value of export and keep the selling price at a level to compete in the market. In this process the domestic industry is not able to recover its marginal cost, therefore, the domestic industry is unable to sell the subject goods at such a low price resulting loss of contract. Hence, the

Authority notes that due to the dumped price, the domestic industry is forced to sell the product at a loss.

Price undercutting, Price suppression/depression and Price underselling

78. On the basis of the evidence available before the Authority, it is determined that the domestic industry has suffered injury. It has been observed that the dumping has had a significant impact on the net sales realisation of the domestic industry for the subject goods. To preserve its market share, the petitioner had to compete with low priced and dumped imports of the subject goods from the subject countries. Thus dumped imports were undercutting the prices of the domestic industry as landed value of imports from the subject countries was below the selling price of the domestic industry. The Authority notes that the landed price of the dumped imports indicates the evidence of severe price undercutting.

79. The Authority notes that the price underselling is an important indicator to make an assessment of the injury. The Authority has worked out the fair selling price of the product under consideration and compared the same to the landed value to arrive at the extent of price underselling. The analysis shows a significant level incidence of price underselling causing injury to the domestic industry. The imports were having significant suppressing/depressing effect on the price of the domestic market, as the domestic industry is not able to raise its selling price in view of the dumped imports. Thus the examination of the available evidence shows that the domestic industry as a whole suffered injury on its sales of subject goods during POI. The Authority has determined the extent of price undercutting and price underselling during the POI and holds that domestic industry has suffered significant price undercutting and price underselling during the POI due to dumped imports from the subject country.

80. The fair selling price of domestic industry is below the cost of production of subject goods and further imports were thus preventing the domestic industry effecting legitimate price increase. The Authority has determined the extent of Price suppression/depression during the POI and notes that domestic industry has suffered significant price suppression/depression during the POI due to dumped imports from the subject countries.

Employment

81. The employment level of domestic industry has been consistent and the index has more or less at the same level at 95 to 96. The Authority, however, notes that this position in the level of employment cannot be ascertained that led to injury to the domestic industry.

Profitability

82. The unit cost of production has declined from 100 in 1999-2000 to 98.43 in 2000-2001 and further declined to 93.91 during the POI (annualised) whereas unit-selling price has marginally increased from 100 in 1999-2000 to 100.16 during the POI (annualised).

83. The cost of production of the domestic industry has declined whereas selling price has improved its position. The domestic industry is incurring financial losses but profitability of domestic industries has improved due to the financial restructuring and reducing cost on account of interest of one of the petitioner companies. It is also observed that the domestic industry could not recover the loss even after the subject goods are attracting anti dumping duty on Chinese imports, which is an indication that the recovery of the domestic industry is prevented due to the new source of alleged dumping. The domestic industry has improved a bit in its financial health due to improvement in loss, still the domestic industry is forced to reduce the selling price to hold on markets due to dumped imports from subject countries.

Growth and return in investment

84. The demand for the product has increased however, the growth of the domestic industry has declined. The imports are retarding the growth of the domestic industry in spite of increase in demand in the country. It is noted that due to dumped imports from subject countries the domestic industry is doubtful to achieve the target or even to raise capital from the market unless remedial measures is taken to prevent dumped imports from subject countries. The Authority notes that it would be difficult for the domestic industry to plan fresh investments.

85. The rate of return on investment during POI for the product under consideration is negative due to loss for the domestic industry, as a result of which the domestic industry has not able to raise fresh capital or plan new investment in this product.

86. Further, the increase in the wages has resulted in further increase in the cost of sales, whereas the domestic industry could not maintain its desired profits. The Authority notes that the domestic industry has no option but to increase wages as per prevailing regulations in the country. However, the wage increases will further affect the profitability adversely, as the domestic industry is not able to proportionately increase the prices.

87. Growth of the domestic industry has declined. Productivity, even though improved, did not help the domestic industry in improving the profitability. The Authority, however, notes that this position in the level of employment cannot be ascertained that led to injury to the domestic industry.

G. Cumulative Assessment

88. It is observed from the facts available on record that the margins of dumping from each of the subject countries are more than the 2% limit expressed as % of export price. Also the volumes of imports from each of the country are more than de minimus. Cumulative assessment of the effects of imports would be appropriate since the exports from the subject countries directly compete with each other and with the goods offered by the domestic industry in the Indian market. The circumstances of the present case fully meet conditions of cumulative assessment given in the Annexure II of the Rules, as (1) margin of dumping from each of subject countries is more than the de minimus limits; (2) share of imports from each of the subject countries is more than the limits prescribed; and (3) the imported material is directly competing with the domestic material. The Authority notes that all relevant factors cumulatively and collectively establish that the domestic industry has suffered the material injury during the period of investigation due to dumped imports.

89. The Authority after noting the above submissions holds that the non-injurious price has been evaluated for the domestic producers by appropriately considering the sales realisation from the related products. Also in order to eliminate inefficiencies, the Authority has normated and benchmarked the best practices on utilisation of raw materials, utilities etc.

90. As regards the injury, which could happen on account of higher cost of production in India, the Authority notes that under

[illegible]

Import									
Share of subject countries		17.51		10.96		36.20		36.20	
Other countries		82.49		89.04		63.80		63.80	

95. From the above table it is observed that the share of volume of dumped imports in total consumption has increased from 0.62% in 2000-2001 to 2.5% during POI, whereas the market share of domestic industry fell from 53.55% in 1999-2000 to 48.31% during the POI. The dumped imports were coming into India at price that significantly undercut the prices of like domestic product. Thus the prices of dumped imports have caused both price depression and price suppression on the prices of like domestic products.

96. There is no contraction in demand. Further, there is no other factor such as trade restrictive practice or development in technology, which could have caused material injury to the domestic industry. Increase in imports in absolute terms, as also relative to the production and consumption in India, have directly resulted increase in the sales, which further resulting in decline in the share of the domestic industry in the demand of the product in the country. Further, the low prices of imports have prevented the domestic industry from optimising their profitability.

97. The Authority, therefore, notes from the above that the landed value of imports from the subject countries have been at a price below the selling price of the domestic industry. Further, the imports into India have been at a price lower than the non-injurious price for the domestic industry. As a consequence thereof the domestic industry has not been able to earn a reasonable return. These parameters collectively and cumulatively indicate that the petitioner has suffered material injury due to the dumped imports.

I. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

98. The Authority holds that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

99. The Authority also recognises that though the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products, however, fair competition in the Indian market will not be reduced by these anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by the dumping practices and would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice of the subject goods to the consumers.

100. The Authority notes that the imposition of anti-dumping measures would also not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

101. The Authority has not merely relied upon the submissions of the petitioners regarding fair selling price, rather the Authority deputed a team for on-the-spot investigation and verification of costing and manufacturing process of Sodium Hydrosulphite, and worked out in detail the fair selling price of Sodium Hydrosulphite in India for the Domestic Industry separately.

102. Consumers have raised their arguments that the imposition of anti dumping measures would result in less competition and higher prices for consumers of caustic soda and may harm the user industry. The Authority notes that price advantages based on unfair practices are unjustifiable and may in the longer term are harmful even to the interest of consumer.

J. CONCLUSIONS:

103. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that:

- (i) Subject goods have been exported to India from subject countries below its normal value;
- (ii) The Indian industry has suffered material injury ;
- (iii) The injury has been caused cumulatively by the imports from the subject countries.

104. The Authority considers it necessary to impose an anti dumping duty on all imports of Sodium Hydrosulphite from subject countries in order to remove the injury to the domestic industry. The margin of dumping determined by the Authority is indicated in the paragraphs above. The Authority recommend the amount of anti dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining injury, the landed value of imports has been compared with the weighted average non-injurious price of the Petitioner Companies determined for the period of investigation.

105. Accordingly, the Authority recommends that the anti dumping duties as set out below be imposed by the Central Government on all imports of subject goods under consideration falling under customs heading 2831.10 originating in or exported from subject country. The Anti-Dumping duty shall be the difference between the amount mentioned in column no.9 of the following table and the landed value of imports US\$ per MT. on all imports of subject goods, falling under chapter 28 of the Customs Tariff, originating in or exported from the subject countries mentioned below:-

Sl. No (1)	Sub- heading (2)	Description of goods (3)	Specification (4)	Country of origin (5)	Country of Export (6)	Producer (7)	Exporter (8)	Amount (9)	Unit Measurement (10)	Currency (11)
1	2831.10	Sodium Hydrosulphite		Germany	Any other Country than Korea,RP	M/s. BASF, Germany	M/s. BASF, Germany	1034.76	Metric Tonne	
2	2831.10	Sodium Hydrosulphite		Germany	Any other Country than Korea,RP	M/s. BASF, Germany	Any Exporter	1034.76	Metric Tonne	USD
3	2831.10	Sodium Hydrosulphite		Germany	Any other Country than Korea,RP	Any Producer	M/s. BASF, Germany	1034.76	Metric Tonne	USD
4	2831.10	Sodium Hydrosulphite		Any country other than Germany	Germany	Any Producer Other than M/s. BASF, Germany	Any Exporter Other than M/s. BASF, Germany	1034.76	Metric Tonne	USD
5	2831.10	Sodium Hydrosulphite		Germany	Any other Country than Korea,RP	Any Producer Other than M/s. BASF, Germany	Any Exporter Other than M/s. BASF, Germany	1034.76	Metric Tonne	USD
6	2831.10	Sodium Hydrosulphite		Korea, RP	Any other Country than Korea, RP	Any Producer	Any Exporter	1034.76	Metric Tonne	USD
7	2831.10	Sodium Hydrosulphite		Any country other than Korea RP	Korea, RP	Any Producer	Any Exporter	1034.76	Metric Tonne	USD

106. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.
107. Subject to the above, the Authority confirms the Preliminary Findings dated 25th February 2003.
108. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Act, supra.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority